नई दिल्ली ■ शुक्रवार 06 फरवरी 2026 ■ मूल्य 5.00 ■ वर्ष 13 ■ अंक 310 ■ पृष्ठ 08

JBT जनभावना टाइम्स

www.thejbt.com

निष्पक्ष और निर्भीक खबर

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गौतमबुद्ध नगर, देहरादून, लखनऊ, अलीगढ़, मथुरा, हिसार, कैथल एवं करनाल से प्रकाशित

04 ऑनलाइन गेमिंगः मनोरंजन से लत और लत से त्रासदी तक | 07 मैनचेस्टर सिटी काराबाओ कप के फाइनल में | बालाजी मोशन पिक्चर्स के साथ बॉलीवुड डेब्यू करेंगी सुनीता आहूजा 08

कांग्रेस कभी मेरी कब्र नहीं खोद पाएगी: मोदी

भारत प्रतिस्पर्धा को तैयार, दुनिया के देश व्यापारिक संबंध बनाने को आतुर : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि विपक्षी दल लगातार चुनावी हार को पचा नहीं पा रहा है और उनके प्रति गहरी नफरत रखने के बावजूद वह कभी उनकी कब्र नहीं खोद पाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार है और दुनिया के देश भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने को आतुर हैं। भारत-यूरोपीय संघ के बीच हुए समझौते ने दुनिया को भरोसा दिया है और अमेरिका के साथ हुए व्यापारिक समझौते ने इसे गति का एहसास कराया है। वर्तमान में दुनिया में वैश्विक दक्षिण (विकासशील देश) चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसका सूत्रधार भारत है और वैश्विक मंचों पर उनकी आवाज बुलंद कर रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर दिया। उन्होंने राहुल गांधी के राजनीतिक नारे 'मोहब्बत की दुकान' को जुमला बताया और कहा कि ऐसा कहने वालों के अंदर असल में नफरत भरी है। विपक्ष उनकी सरकार की उपलब्धियां के चलते 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी' के नारे लगा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग मुझे पूछते हैं कि मेरी सेहत का राज क्या है और मैं कहता हूं कि मैं रोज दो किलो गाली खाता हूं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस नेतृत्व पर तंज कसा और कहा कि चोरी इनका पुश्तैनी पेशा रहा है और उन्होंने एक गुजराती (महात्मा गांधी) का सरनेम चुरा लिया। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के भाजपा नेता नवनीत सिंह बिट्टू को 'गद्दार' कहे जाने की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सदन के एक सदस्य को सिख होने के कारण ऐसा कहा गया। उन्होंने कांग्रेस पर भारत रत्न भूपेन हजारिका का अपमान करने का भी आरोप लगाया।

प्रधानमंत्री ने कल लोकसभा में पेपर उछाले जाने की घटना का भी उल्लेख किया और कहा कि विपक्ष ने इस दौरान चेयर पर मौजूद पूर्वोत्तर के एक साथी और आंध्र प्रदेश के एक दलित सदस्य का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कितने ही टुकड़े हुए हैं, कितने लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, लेकिन किसी और को उन्होंने (राहुल गांधी) गद्दार नहीं कहा। उन्होंने उस सदस्य (बिट्टू) को गद्दार इसलिए कहा, क्योंकि वे एक सिख हैं। यह सिखों का अपमान था, गुरुओं का अपमान था। कांग्रेस में सिखों के प्रति जो कूट-कूटकर नफरत भरी हुई है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान पहले विपक्ष ने शोर-शराबा किया और कुछ समय बाद सदन से बाहिर्गमन किया। बाकी समय प्रधानमंत्री ने विपक्ष की अनुपस्थिति में चर्चा का जवाब दिया। नारेबाजी के दौरान प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के खड़े होकर नारे लगाने पर कहा कि उनकी आयु अधिक है और वे चाहते हैं कि वे अपनी सीट पर बैठकर नारे लगाएं। वहीं विपक्ष के बाहर जाने पर उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले थक के बाहर चले गए हैं।

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में राज्यसभा सदस्य सदानंद मास्टर के चर्चा में भाग लेने और पहली बार सदन में बोलने पर उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि वैचारिक असमानता के कारण एक शिक्षक (सदानंद मास्टर) के पैर काट दिए गए। इसके लिए इंडी अलायंस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कटे हुए पैर से वे जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन संस्कार इतने ऊंचे हैं कि वाणी में भी अपशब्द नहीं निकलता है। ऐसे व्यक्तित्व को, सदानंदन जी मास्टर को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। क्योंकि इतने हमले के बाद भी देश की सेवा का अपना व्रत जारी रखा और आज देश के नीति-निर्धारण में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि विडंबना की बात है कि खुद को राजा मानने वाले असमानता की बात कर रहे हैं। 'कुछ लोग खुद को राजा मानते हैं और आर्थिक असमानता की बात कर रहे हैं, यही दिन देखने को रह गए थे।'

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी सदस्य सदन में घुसपैठियों की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के समृद्ध देश अपने यहां से गैरकानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। वहीं हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों पर प्रेशर डाला जा रहा है। देश का नौजवान ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में सत्ता में आने पर बैंकिंग क्षेत्र में गैर निष्पादित संपत्ति बहुत ज्यादा थी। उनकी सरकार के प्रयास से आज यह 1 प्रतिशत से भी नीचे आ गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के निगम आज संभल रहे हैं। आज नीति आयोग बहुत तेजी से काम कर रहा है। आकांक्षी जिलों से जुड़ी योजना दुनिया के लिए प्रेरणा बन रही है। प्रगति प्लेटफार्म से देश के विकास को गति मिली है और 85 लाख करोड़ की अटकी परियोजनाएं पूरी हुई हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव बिना जवाब के ही ध्वनिमत से पारित

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्षी दलों के आठ सदस्यों के निलंबन और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने देने की मांग पर हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर 02 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। इस दौरान हंगामे के बीच सदन ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को बिना जवाब के ही ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार को पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्हें कई स्थगन प्रस्तावों की सूचना मिली है, लेकिन किसी को अनुमति नहीं दी गई। इस दौरान नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपद यशो नाईक, सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री सुरेश गोपी ने अपने-अपने मंत्रालयों से जुड़े दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियां लेकर सदन के बीचोंबीच पहुंच गए और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों को चेतावनी दी कि हाथों में तख्तियां लेकर आने पर उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अनेक संशोधन प्रस्तुत किए गए, जिन्हें मतदान के बाद अस्वीकृत कर दिया गया। इस दौरान हंगामे के बीच ही धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से अपील की कि वे सदन को चलने दें और सभी को बजट पर बोलने का अवसर दें। उन्होंने कहा कि लगातार हंगामा करना सदन का अपमान है लेकिन विपक्षी सदस्यों के विरोध के चलते कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया।

मेघालय के अवैध कोयला खदान में धमाके से 16 मजदूरों की मौत

शिलांग। मेघालय में गुरुवार को पूर्वी जयंतिया हिल्स जिलांतर्गत ताशखाई में एक अवैध कोयला खदान में हुए बड़े धमाके में कम से कम 16 मजदूरों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। माना जा रहा है कि जैसे-जैसे राहत कार्य तेज होगा, मृतकों की संख्या में और इजाफा हो सकता है।

घटनास्थल से मिली वीडियो क्लीप में मौके पर मौजूद मजदूर रोते हुए चीख-चीख कह रहे हैं कि खदान के अंदर सैकड़ों मजदूर फंसे हुए हैं। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, धमाका कोयला खदान के अंदर हुआ, जिससे मौके पर मौजूद मजदूरों में भारी जान-माल का नुकसान हुआ। अधिकारियों को शक है कि ज्यादातर पीड़ित असम के मजदूर थे। गुवाहाटी स्थित प्रथम बटालियन एनडीआरएफ मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया है कि हादसे की सूचना मिलते ही मेघालय में मौजूद एनडीआरएफ की एक टीम को राहत एवं बचाव कार्य के लिए घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। साथ ही दो टीमें गुवाहाटी से मेघालय के लिए रवाना किया गया है। दोनों टीमों का नेतृत्व प्रथम बटालियन के सीओ एवं बटालियन के डॉक्टर के साथ ही अन्य अधिकारी कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मेघालय पुलिस ने घटना के बाद बचाव अभियान शुरू कर दिया है और टीमों को इलाके में भेजा गया है।

खदान से काला धुआं निकलता दिख रहा है और मजदूर मौके के आसपास दिख रहे हैं। जो मजदूर बाहर हैं, वे मौके पर इकट्ठा हो रहे हैं। मौके पर कुछ महिलाएं और बच्चे भी रोते-चिल्लाते दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि खदान के अंदर डायनामाइट का इस्तेमाल किया गया होगा, जो अवैध रूप से चल रही थी। तीन मृत मजदूरों की पहचान कर ली गई है। उनकी पहचान असम के काटिगोरा के बिहारा गांव के रहने वाले फारूक अहमद और शरिशा कुरी गांव के रहने वाले दिलदार हुसैन और अनवर हुसैन के रूप में हुई है। एसपी विकास कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि अब तक 16 शव बरामद किए जा चुके हैं और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। अधिकारियों को डर है कि खदान के अंदर और भी शव फंसे हो सकते हैं। यह घटना कोयला खदान में एक शक्तिशाली धमाके के बाद हुई, जिससे बड़े पैमाने पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स शुरू किया गया। पुलिस और बचाव कर्मी मौके पर मौजूद हैं और तलाशी अभियान जारी है।

संक्षिप्त खबरें

चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षकों से कहा- पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करें

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनावों में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले सामान्य, पुलिस तथा व्यय पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। यहां के भारतीय निर्वाचन प्रबंधन संस्थान में गुरुवार से शुरू यह दो दिवसीय बैठक तीन चरणों में होगी। आयोग के अनुसार कुल 1,444 अधिकारियों को ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया है, जिनमें 714 सामान्य पर्यवेक्षक, 233 पुलिस पर्यवेक्षक और 497 व्यय पर्यवेक्षक शामिल हैं। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों को संबोधित किया।

छत्तीसगढ़: बीजापुर में 54 लाख के 12 इनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में गुरूवार को 54 लाख के इनामी 12 नक्सलियों ने पुलिस के आलाधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 08 महिला और 4 पुरुष कैडर के नक्सली शामिल हैं। इन्होंने 3 आटोमैटिक हथियार, कारतूस और विस्फोटक पुलिस को सौंपें। बीजापुर में सुरक्षाबलों के संयुक्त प्रयास से आज साउथ सब जोनल ब्यूरो से संबंधित कुल 54 लाख रूपये की इनामी 8 महिला और 4 पुरुष कैडर के 12 नक्सलियों, जिसमें डीवीसीएम-1 सदस्य, बटालियन नम्बर 1, कंपनी नम्बर दो-2, पीपीसीएम-1, एसीएम -2, पार्टी सदस्य-2, पीएलजीए सदस्य-4 ने 3 आटोमैटिक हथियार, कारतूस व विस्फोटक के साथ बस्तर आईजी सुंदरराज पट्टलिंगम, बीजापुर एसपी डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव, उप पुलिस महानिरीक्षक केरिपु ऑप्स बीजापुर सेक्टर बीएस.नेगी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

ओडिशा: चेन्नई-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस की तीन बोगियां पटरी से उतरीं

भुवनेश्वर। ओडिशा के जाजपुर जिले में जखपुरा रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार सुबह चेन्नई-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस की तीन बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, हादसे के समय ट्रेन की गति काफी धीमी थी। ट्रेन संख्या 22611, जो चेन्नई सेंट्रल (एमएएस) से न्यू जलपाईगुड़ी (एनजेपी) के बीच संचालित होती है, जखपुरा यार्ड सीमा के भीतर दुर्घटनाग्रस्त हुई। रेलवे सूत्रों ने बताया कि एक एसी कोच और दो सामान्य कोच पटरी से उतरे। इस घटना में किसी भी यात्री के हताहत या घायल होने की कोई सूचना नहीं है। साथ ही, इस खंड में यात्री ट्रेनों का परिचालन प्रभावित नहीं हुआ। रेलवे सूत्रों ने बताया कि प्रभावित बोगियों को अलग किया जा रहा है और उनमें सवार यात्रियों को वैकल्पिक रूप से समायोजित किया गया है। यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त बोगियों की व्यवस्था कर उन्हें आवश्यकता अनुसार ट्रेन में जोड़ा जाएगा।

हत्या की तरह है चाइनीज मांझे से होने वाली मौत : सीएम योगी

लखनऊ। प्रदेश में चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। उनका मानना है कि किसी व्यक्ति की चाइनीज मांझे की वजह से होने वाली मृत्यु हत्या की तरह है। इस तरह के मामलों में संबंधित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि चाइनीज मांझा पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसके बावजूद इसकी उपलब्धता गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने पुलिस को प्रदेशव्यापी सघन छापेमारी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान चाइनीज मांझे की बिक्री ही नहीं, बल्कि भंडारण व परिवहन पर भी कठोर नजर रखी जाएगी। सीएम योगी ने प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाकर चाइनीज मांझे की आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह तोड़ने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस अभियान की प्रगति और कार्रवाई की उच्च स्तर पर नियमित समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जनता की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। सीएम योगी के सख्त रुख को देखते हुए प्रदेश भर में छापेमारी शुरू हो गई है।

राजधानी लखनऊ में पुलिस अधिकारियों ने चाइनीज मांझा बेचने वाली दुकानों की छानबीन की और जब्ती की कार्यवाही भी की। इसी प्रकार की कार्यवाही प्रदेश के अन्य जिलों में भी की जा रही है।

देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा 'भारत टैक्सी' का शुभारंभ

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को विज्ञान भवन से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा 'भारत टैक्सी' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी को आगामी तीन वर्षों के भीतर पूरे देश में शुरू किया जाएगा और यह टैक्सी चालकों के आर्थिक सशक्तीकरण का एक बड़ा माध्यम बनेगी।

अमित शाह ने कहा कि फिलहाल भारत टैक्सी की शुरुआत गुजरात के कुछ शहरों के साथ दिल्ली और एनसीआर में की जा रही है लेकिन अगले तीन साल से भी कम समय में यह देश के हर राज्य और प्रमुख शहरों में उपलब्ध होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक भारत टैक्सी टैक्सी चालकों के कल्याण का एक सशक्त मॉडल बनेगी। टैक्सी चालकों को 'सारथी' की संज्ञा देते हुए शाह ने कहा कि अभी तक उनकी टैक्सी का पहिया किसी और की कमाई करता था, लेकिन भारत टैक्सी के माध्यम से अब वही पहिया उनकी अपनी कमाई और समृद्धि के लिए घूमेगा। उन्होंने कहा कि सहकार टैक्सी जो भी मुनाफा कमाएगी, उसमें से तीन वर्ष बाद केवल 20 प्रतिशत राशि सहकार टैक्सी के पास रहेगी, जबकि शेष 80 प्रतिशत राशि प्रति किलोमीटर की औसत के आधार पर सीधे सारथियों के खातों में स्थानांतरित की जाएगी।

सहकार टैक्सी के मालिक भी स्वयं सारथी ही होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत टैक्सी देश की माताओं और बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने 'सारथी दीदी' की अवधारणा का उल्लेख करते हुए बताया कि ऐप पर एक अलग विंडो के माध्यम से महिला यात्रियों के लिए महिला चालक उपलब्ध कराई जाएंगी।

पुलिस की जांच में खुलासा- फिल्म जगत के पांच नामी शख्स अंडरवर्ल्ड के निशाने पर

मुंबई। फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग मामले की छानबीन में पता चला है कि पांच नामी फिल्मी हस्तियां भी अंडरवर्ल्ड के निशाने पर हैं। इन पांचों को रंगदारी के लिए धमकी दिए जाने की जानकारी मुंबई पुलिस को मिली है, लेकिन इनमें से किसी ने भी अब तक पुलिस संपर्क नहीं किया है। इससे पुलिस स्तब्ध हैं, हालांकि पुलिस इस संबंध में सतर्क होकर आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

फिल्म निर्माता रोहित के आवास पर हुई फायरिंग मामले की छानबीन कर रहे अधिकारी ने बताया कि फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के आवास पर रविवार को आधी रात में अज्ञात आरोपितों ने पर 6 राउंड फायरिंग की थी। इस मामले में पुलिस ने पुणे से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली है कि सिर्फ रोहित शेट्टी ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के 5 बड़े स्टार्स गैंगस्टर्स के निशाने पर हैं।

कस्टम विभाग के 3 अधिकारियों पर घूसखोरी का मामला दर्ज

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मिजोरम के चाम्फाई में तैनात रहे कस्टम विभाग के तीन अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया है। इनमें एक रिटायर्ड एसपी रैंक का अधिकारी और दो इंस्पेक्टर शामिल हैं। तीनों के नाम तुआंजाखुप (तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट, कस्टम प्रिवेंटिव फोर्स), मोहन सिंह (तत्कालीनइंस्पेक्टर, कस्टम प्रिवेंटिव फोर्स), साहिल कुमार सिन्हा (तत्कालीन इंस्पेक्टर, कस्टम प्रिवेंटिव फोर्स) हैं।

ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता

वेनेजुएला समेत किसी भी नए विकल्पों के मूल्यांकन के लिए तैयार : भारत

नई दिल्ली। भारत ने कहा है कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा है। वह वेनेजुएला समेत किसी भी नए आपूर्ति विकल्प के वाणिज्यिक लाभों का मूल्यांकन करने के लिए तैयार है।

भारत ने दोहराया कि वह ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाने का पक्षधर है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को यहां साप्ताहिक पत्रकार वार्ता में एक बार फिर ऊर्जा जरूरतों और लाभकारी मूल्यों को निर्णय का आधार बताया। उन्होंने दोहराया कि भारत आपूर्ति में विविधता लाने का पक्षधर है। भारत की इस टिप्पणी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत रूसी तेल खरीदी बंद करने पर सहमत हो गया है। उल्लेखनीय है कि भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में व्यापार समझौता सम्पन्न हुआ है। समझौते के बाद अमेरिका ने भारतीय समानों पर लग रहा अतिरिक्त टैरिफ हटा लिया है।

वहीं ट्रम्प ने दावा किया है कि भारत रूस से तेल खरीदी नहीं करेगा और वेनेजुएला को प्राथमिकता देगा। जायसवाल ने भारत अमेरिकी समझौते से जुड़े कई प्रश्नों के उत्तर दिए। प्रवक्ता ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर कहा कि ऊर्जा आपूर्ति के संबंध में सरकार ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से बयान दिया है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत की रणनीति रही है कि अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाजार स्थितियों और बदलते वैश्विक घटनाक्रम के अनुरूप ऊर्जा स्त्रोतों में विविधता लाए।

5 तेजस लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे जाने के लिए तैयार : एचएएल

नई दिल्ली। सरकारी एयरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने बृहस्पतिवार को कहा कि पांच तेजस हल्के लड़ाकू विमान भारतीय वायु सेना को सौंपने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रक्षा मंत्रालय ने फरवरी 2021 में वायु सेना के लिए 83 तेजस एमके-1ए लड़ाकू विमान खरीदने के लिए एचएएल के साथ 48,000 करोड़ रुपये का करार किया था।

हालांकि जीई एयरोस्पेस द्वारा इंजन की आपूर्ति कई समय सीमाओं के बावजूद नहीं होने की वजह से इन लड़ाकू विमानों की आपूर्ति में देरी हो रही है। एचएएल की एक प्रवक्ता ने बताया कि एचएएल पुष्टि करती है कि पांच विमान आपूर्ति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिनमें अनुबंधित विशिष्टताओं के अनुसार प्रमुख क्षमताएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नौ अतिरिक्त विमान पहले ही बनकर तैयार हो चुके हैं और उनका परीक्षण भी हो चुका है। जीई से इंजन प्राप्त होते ही ये विमान आपूर्ति के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रवक्ता ने बताया कि डिजाइन और विकास से संबंधित सभी समस्याओं का तेजी से समाधान किया जा रहा है। तेजस एकल इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो उच्च खतरे वाले हवाई वातावरण में अपने मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। इसे वायु रक्षा, समुद्री टोही और आक्रमणकारी भूमिकाओं को निभाने के लिए डिजाइन किया गया है।

प्रवक्ता ने कहा कि एचएएल विमान की जल्द से जल्द आपूर्ति के लिए भारतीय वायु सेना के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि एचएएल को अबतक जीई से पांच इंजन प्राप्त हो चुके हैं। जीई की आपूर्ति की स्थिति सकारात्मक है, और भविष्य में आपूर्ति एचएएल की योजनाओं के अनुरूप है। प्रवक्ता ने कहा कि एचएएल आश्वस्त करता है कि वह चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर लेगा।

चेक बाउंस मामला

अभिनेता राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया

नई दिल्ली। अभिनेता राजपाल यादव ने चेक बाउंस मामले में बृहस्पतिवार को यहां तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामलों में जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए दी गई समयसीमा को बढ़ाने से इनकार कर दिया था। तिहाड़ जेल के एक सूत्र ने कहा कि अभिनेता ने बृहस्पतिवार शाम चार बजे जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब जेल अधिकारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करेंगे।

रोहिल्लापुर के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण पर चला ग्रेनो प्राधिकरण का बुल्डोजर

करीब 18,000 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया, डूब क्षेत्र में अवैध कालोनी बसाने की फिराक में थे कालोनाइजर

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बृहस्पतिवार को रोहिल्लापुर के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ प्राधिकरण का बुल्डोजर चला और करीब 18 हजार वर्ग मीटर डूब एरिया पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर परियोजना व भूलेख विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है। कालोनाइजर प्लॉटिंग कर अवैध कालोनी बसाने के फिराक में थे। ग्रेनो प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने चेतावनी दी है कि अधिसूचित एरिया में अनुमति के बिना या फिर बिना नक्शा पास कराए बिना अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई जारी रहेगी।

एसीईओ ने अपील भी की है कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण के भूलेख विभाग से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। अवैध कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं।

दरअसल, रोहिल्लापुर के खसरा संख्या 22 व 33 की करीब 18000 वर्ग मीटर जमीन हिंडन के डूब क्षेत्र में है। यह प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में है। कुछ कालोनाइजर डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण कर कालोनी काटने की कोशिश कर रहे थे। प्राधिकरण के परियोजना विभाग के वर्क सर्किल 3 की टीम ने पुलिस के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। वर्क सर्किल-3 के प्रभारी राजेश कुमार निम के नेतृत्व में प्रबंधक लव शंकर भारती व टीम ने प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में बुल्डोजर से करीब दो घंटे की कार्रवाई में इसे ध्वस्त कर दिया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एके सिंह ने बताया कि डूब क्षेत्र में प्लॉटिंग होने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई है।

अतिक्रमण पर 15 दिन में 5 बड़ी कार्रवाई

45 हजार वर्ग मीटर जमीन से मुक्त, 8 रिहायशी टॉवरों को भी किया सील

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने विगत 15 दिनों में अतिक्रमण के खिलाफ 5 बड़ी कार्रवाई की है। विगत 20 जनवरी को भनौता में 11340 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। इसी तरह 28 जनवरी को हैबतपुर में 6000 वर्ग मीटर, 04 फरवरी को भनौता में 10 हजार वर्ग मीटर और अब बृहस्पतिवार को रोहिल्लापुर में 18 हजार वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। वहीं, 29 जनवरी को खेड़ा चौगानपुर में 8 टॉवरों के 100 से अधिक फ्लैटों को सील किया गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए लगातार हो रही कार्रवाई से कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया है। प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने कहा है कि अधिसूचित एरिया में प्राधिकरण की अनुमति के बिना निर्माण नहीं किया जा सकता। अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण का ध्वस्तीकरण अभियान जारी रहेगा।

संक्षिप्त खबरें

दहेज हत्या के आरोपित पति समेत तीन गिरफ्तार

नोएडा। थाना जारचा क्षेत्र में दहेज के लिए विवाहिता की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उन्हें आज कोर्ट में पेश कर दिया है। थाना जारचा के प्रभारी निरीक्षक कैलाश नाथ ने बताया कि चार दिन पूर्व एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसके ससुराल में फंदे से लटका हुआ मिला था। इस मामले मे मायके पक्ष के लोगों ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। घटना के बाद से महिला के ससुराल पक्ष के लोग फरार चल रहे थे। उन्होंने बताया कि मामले की जांच कर रही पुलिस ने बीती रात को दहेज हत्या के आरोपित ससुर गोपाल, पति लोकेश और जेठ उमेश को एनटीपीसी के पास से गिरफ्तार कर लिया है। लोकेश की शादी शिवानी से वर्ष 2025 में हुई थी। उसके पिता का आरोप है की शादी के समय से ही उसकी बेटी के ससुराल पक्ष लोग दहेज के लिए उसका उत्पीड़न कर रहे थे। उनके उत्पीड़न के चलते उसने आत्महत्या किया है।

नोएडा में अवैध देशी शराब पर पुलिस का शिकंजा, दो गिरफ्तार

नोएडा। नोएडा में अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के पास से कुल 90 पव्वे देसी शराब बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया है। थाना सेक्टर-63 पुलिस प्रभारी अमित कुमार के मुताबिक, गश्त के दौरान टीम ने मेट्रो पिलर के पास संदिग्ध हालत में खड़े एक युवक को रोका और तलाशी ली। तलाशी में उसके पास से ट्विन टावर ब्रांड के 50 पव्वे देसी शराब बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अनिल कुमार (पुत्र संतोष, निवासी औरैया) बताया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह फिलहाल छिजारसी कॉलोनी में रह रहा था और काफी समय से इलाके में अवैध रूप से देसी शराब बेचने में लगा हुआ था। दूसरी कार्रवाई थाना सेक्टर-142 क्षेत्र में हुई। थाना प्रभारी विनोद मिश्र ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने सेक्टर-140, FNG रोड से एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान टुन्नू कुमार (पुत्र खजानती पासवान, निवासी ग्राम इलाहाबास) के रूप में हुई है। उसके पास से टेट्रा पैक 'दोस्ताना' देसी शराब के 40 पव्वे बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह ठेके से शराब खरीदकर लाता था और रात में ठेके बंद होने के बाद अधिक दामों पर बेचकर मुनाफा कमाता था।

कई सेक्टर में शुक्रवार को पांच घंटे बिजली कटौती

नोएडा। विद्युत निगम ने 33 हजार किलोवाट की लाइन पर काम करेगा। इसके चलते शुक्रवार को पांच घंटे बिजली कटौती होगी। सेक्टर-72, 73, 75, 121 और सरफाबाद, बसई और गढ़ी चौखंडी गांव में सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

बच्चों ने गुड़िया संग्रहालय का भ्रमण किया

ग्रेटर नोएडा। जीडी गोयंका पब्लिक स्कूल के कक्षा प्री-नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों ने बुधवार को शैक्षिक भ्रमण के लिए दिल्ली स्थित गुड़िया संग्रहालय का दौरा किया। बच्चों ने यहां विभिन्न प्रकार की नई और सुंदर गुड़ियां के बारे में जाना। प्रधानाचार्या डॉ. रेणु सहगल ने बच्चों को म्यूजियम के बारे में जानकारी दी। यह भ्रमण बच्चों के लिए काफी ज्ञानवर्धक और आनंददायक रहा।

नानकेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि मेला 11 से

रबूपुरा। भाईपुर ब्रह्मनान गांव के नानकेश्वर महादेव शिव मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेला 11 से 16 फरवरी तक चलेगा। 15 फरवरी को त्रयोदशी व 16 फरवरी शिव चौदस को कांवड़ (जल) चढ़ाई जाएगी। मेले में दंगल का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें इनामी मुकाबले होंगे और लोगों को नामी पहलवानों की कुश्तियां देखने को मिलेंगी। मेला कमेटी के अध्यक्ष राजेश सिंह ने बताया कि हवन, आरती, प्रवचन समेत विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे। दंगल 12 और 13 फरवरी को होगा। इसमें हरियाणा, दिल्ली, बुलंदशहर, नोएडा व ग्रेटर नोएडा के साथ-साथ अन्य प्रदेशों के पहलवान शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि मेले में लोगों के मनोरंजन के लिए झूला, नौटंकी, सर्कस आदि भी लगाए जाएंगे। कांवड़ियों के स्नान, ठहरने और जल चढ़ाने की विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही हर साल की तरह अन्य राज्यों से आने वाले शिव भक्तों के लिए दर्शन की विशेष व्यवस्था की जा रही है। रबूपुरा से 6 किमी दूर यमुना की तलहटी पर बने इस प्राचीन शिव मंदिर का इतिहास महाभारत कालीन है। मान्यता है कि पांडवों ने यहां पर अपना कुछ समय बिताया था। नानकेश्वर महादेव मंदिर में लगने वाला मेला गौतमबुध नगर का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। अन्य प्रदेशों से भी श्रद्धालु यहां आते हैं। फाल्गुन मास में शिव चौदस के 10 दिन बाकी रहने के कारण मेले की तैयारियां जोरों पर है।

राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पंच लगाएंगी जिया

ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर की बॉक्सर जिया बैसोया कर्नाटक में आयोजित स्कूली राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता के लिए बॉक्सर का चयन राज्यस्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के आधार पर हुआ है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से कर्नाटक के बंगलुरू स्थित सेंट क्लैरेट प्री विश्वविद्यालय में 6 से 9 फरवरी तक राष्ट्रीय स्कूली मुक्केबाजी (अंडर-19) चैंपियनशिप कराई जाएगी। ग्रेटर नोएडा के दादरी स्थित सादोपुर गांव निवासी जिया बैसोया भी अंडर-19 कैटेगरी में उत्तर प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनके पिता विकास बैसोया ने बताया कि लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 24 से 26 सितंबर 2025 तक राज्य स्कूली बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बेटी ने अंडर-19 कैटेगरी में खेलते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया था। उसी के आधार पर उसका चयन यूपी बॉक्सिंग प्रशिक्षण शिविर के लिए हुआ। शिविर में भी बेहतर प्रदर्शन करने पर जिया ने यूपी टीम में अपना स्थान पक्का किया है। वह शुक्रवार से राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के लिए रिंग में उतरेंगी।

विभिन्न सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत

नोएडा। उत्तर प्रदेश के जनपद नोयडा के विभिन्न जगहों पर हुए अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई है। घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना बिसरख क्षेत्र के तिगरी गोल चक्कर के पास बीती रात को एक मोटरसाइकिल सवार को एक अज्ञात वाहन चालक ने टक्कर मार दिया। इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक का नाम आदेश शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा निवासी सिद्धार्थ विहार विजयनगर गाजियाबाद है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की सहायता से घटना को अंजाम देने वाले वाहन चालक की तलाश की जा रही है। थाना जेवर क्षेत्र के गोपालगढ़ के पास पैदल जा रहे एक व्यक्ति को एक अज्ञात वाहन चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए बीती रात को टक्कर मार दिया। इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया।

जिम्स में 'आगाज़-2026' का भव्य शुभारंभ

ग्रेटर नोएडा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (GIMS), ग्रेटर नोएडा में वार्षिक खेल एवं सांस्कृतिक महोत्सव "आगाज़-2026" का गुरुवार को भव्य शुभारंभ हुआ। आठ दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव 5 फरवरी से 12 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। फेस्ट का उद्घाटन दोपहर 1 बजे जीबीयू स्पोर्ट्स ग्राउंड में GIMS के डायरेक्टर डॉ. (ब्रिगेडियर) राकेश गुप्ता ने गुब्बारे उड़ाकर किया। उद्घाटन अवसर पर डीन डॉ. रम्भा पाठक, CMS डॉ. सौरभ श्रीवास्तव, डॉ. सतेंद्र कुमार, डॉ. रंजना वर्मा, डॉ. अपराजिता पंवार, डॉ. इजेन भट्टाचार्य, डॉ. पी.एस. मित्तल, डॉ. बी.एस. यादव, डॉ. भारती भंडारी, डॉ. मानवेंद्र बैद्य, डॉ. पुलिमी विनील, डॉ. अभिषेक भारती, डॉ. सोनू, डॉ. ममता यादव सहित बड़ी संख्या में संकाय सदस्य और रेजिडेंट डॉक्टर मौजूद रहे। इस महोत्सव का आयोजन GIMS स्टूडेंट काउंसिल द्वारा किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता एमबीबीएस बैच 2022 के छात्र अभिषेक कुमार सिंह कर रहे हैं। आगाज़-2026 की शुरुआत के अवसर पर 2023 और 2022 बैच की छात्राओं के बीच गर्ल्स क्रिकेट फाइनल मैच खेला गया। फेस्ट के दौरान फुटबॉल, थ्रोबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट और एथलेटिक्स जैसी कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इसके साथ ही फैकल्टी सदस्य भी बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, शॉटपुट, रस्साकशी, शतरंज और कैरम जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नृत्य, संगीत, नाट्य प्रस्तुति, फैशन शो, क्राफ्ट, पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग सहित कई रचनात्मक गतिविधियां शामिल हैं। फेस्ट के अंतर्गत GIMS, शारदा मेडिकल कॉलेज, NIMS यूनिवर्सिटी और मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के बीच इंटरकॉलेज प्रतियोगिताएं भी होंगी। महोत्सव की श्रृंखला में 4 फरवरी की शाम एमबीबीएस 2025 बैच के लिए फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया गया, जबकि एमबीबीएस 2020 बैच का फेयरवेल 6 फरवरी की शाम GIMS के अकादमिक ब्लॉक में आयोजित किया जाएगा। छात्रों में फैशन शो और सेलिब्रिटी नाइट को लेकर विशेष उत्साह है। इस अवसर पर प्रसिद्ध स्टैंड-अप कॉमेडियन मोहित दुडेगा अपनी प्रस्तुति देंगे। हर वर्ष की तरह "आगाज़" छात्रों और शिक्षकों के लिए शैक्षणिक दबाव से हटकर ऊर्जा, रचनात्मकता और टीमवर्क को प्रोत्साहित करने वाला मंच है।

शारदा विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय एनुअल फेस्ट 'कोरस' का भव्य शुभारंभ, ग्लोबल विलेज बना आकर्षण

ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क स्थित शारदा विश्वविद्यालय में गुरुवार को तीन दिवसीय एनुअल फेस्ट 'कोरस' का भव्य शुभारंभ हुआ। इस फेस्ट में देश-विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की करीब 60 टीमों ने हिस्सा लिया है। तीन दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में शैक्षणिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। फेस्ट के दौरान डीजे और म्यूजिकल नाइट के साथ-साथ बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण ग्लोबल विलेज रहा, जहां भूटान, म्यांमार, नेपाल, बिहार, केरल, कश्मीर, अफ्रीकी देशों समेत 28 देशों के छात्रों ने अपने-अपने देश के पारंपरिक व्यंजन तैयार किए। इस अवसर पर विभिन्न देशों के राजनयिकों की उपस्थिति भी प्रस्तावित है।

फेस्ट का आयोजन इंटरनेशनल डिविजन के डायरेक्टर अशोक दरियानी एवं छात्र कल्याण विभाग के डीन डॉ. प्रमोद कुमार की देखरेख में किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के डायरेक्टर पीआर डॉ. अजीत कुमार ने बताया कि तीन दिवसीय फेस्ट के दौरान 20 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिनमें बहस प्रतियोगिता, फैशन शो, मोनोलॉग, स्टैंड-अप कॉमेडी, रैप वॉर, ओपन-माइक शो सहित कई रचनात्मक प्रतियोगिताएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस फेस्ट में 70 से अधिक देशों के गणमान्य व्यक्ति, संकाय सदस्य और प्रतिभागी शामिल होंगे। गुरुवार शाम को सिंगर अदिति शर्मा और डीजे नाइट में रावाटोर परफॉर्म करेंगे।

वहीं शुक्रवार को सेलिब्रिटी नाइट में सलीम-सुलेमान और शनिवार को पंजाबी नाइट में बॉलीवुड सिंगर सुनंदा शर्मा अपनी प्रस्तुति देंगी। तीन दिवसीय यह महोत्सव विभिन्न संस्थानों के प्रतिभागियों को एक साझा मंच प्रदान कर रहा है, जहां वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के साथ-साथ आपसी संवाद, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और यादगार अनुभव हासिल कर सकेंगे।

एमिटी विवि में स्थायी व्यापार व उद्यमिता पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ

नोएडा। विश्वविद्यालय के एमिटी स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा 5 से 6 फरवरी तक उद्यमिता एवं स्थायी व्यापार विकास पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीईएसबीडी-26) के चतुर्थ संस्करण का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डीएस समूह की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी सिमिन अस्करी, एमिटी विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर डॉ. बलविंदर शुक्ला, मैककेन फूड की स्थायीत्व एवं सामाजिक संचार प्रमुख शरण्या प्रधान, लजुबजाना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. मतेज सेर्न, एमिटी विश्वविद्यालय के एडिशनल प्रो वाइस चांसलर डॉ. संजीव बंसल, बुक माई जेट के संस्थापक एवं सीईओ संतोष शर्मा तथा एमिटी स्कूल ऑफ बिजनेस की निदेशक डॉ. सुजाता खंडाई ने किया।

सम्मेलन के अंतर्गत "नेक्स्ट जेन-इनोवेट एक्सपो 2026" का भी आयोजन हुआ, जिसमें 29 युवा उद्यमियों के सस्टेनेबल और डिजिटल स्टार्टअप्स प्रदर्शित किए गए। वक्ताओं ने गिग इकोनॉमी, स्थायीत्व, डिजिटल परिवर्तन और जिम्मेदार व्यापार मॉडल पर जोर देते हुए कहा कि भविष्य का व्यापार नवाचार और मूल्यों के संतुलन से ही आगे बढ़ेगा। तकनीकी सत्रों में उद्योग विशेषज्ञों ने स्थायी नवाचार पर चर्चा की तथा शोधार्थियों के लिए पेपर विकास कार्यशाला का आयोजन भी किया गया।

आईएमएस नोएडा में साइबर सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम

नोएडा। सेक्टर 62 स्थित आईएमएस नोएडा के स्कूल ऑफ आईटी ने सुरक्षित एवं जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार के प्रति छात्रों को जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान बतौर वक्ता सी-डैक के साइबर सिक्युरिटी इंजिनियर शुभम त्रिपाठी ने अपने विचार प्रकट किए। वहीं कार्यक्रम के दौरान छात्रों को उभरते साइबर खतरों, डेटा सुरक्षा, ऑनलाइन सेफ्टी तथा साइबर अपराध से बचाव के प्रभावी उपायों पर चर्चा की गयी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आईएमएस की डीन प्रोफेसर (डॉ.) नीलम सक्सेना ने कहा कि आज के डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि प्रत्येक छात्र की सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेदारी है। तकनीक का उपयोग ज्ञानवर्धन के साथ-साथ सुरक्षित, सतर्क एवं नैतिक तरीके से किया जाना अत्यंत आवश्यक है। वहीं संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर (डॉ.) विकास धवन ने कहा कि डिजिटल तकनीक के तेजी से विस्तार के साथ साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता समय की आवश्यकता बन गई है। छात्रों को संभावित खतरों से अवगत रहने के साथ-साथ जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने की जरूरत है। शुभम त्रिपाठी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी डिजिटल दुनिया का सक्रिय हिस्सा हैं, इसलिए अपनी ऑनलाइन पहचान और डेटा की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज के साइबर परिदृश्य में केवल सिस्टम का उपयोग जानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी सुरक्षा संरचना को समझना भी उतना ही जरूरी है। मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एन्क्रिप्शन, नियमित सिस्टम अपडेट और सुरक्षित नेटवर्क प्रैक्टिसेज अपनाकर हम स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने छात्रों से मजबूत पासवर्ड का उपयोग करने, किसी भी अनजान लिंक या कॉल पर भरोसा नहीं करने एवं सोशल मीडिया पर सोच-समझकर जानकारी साझा करने की अपील की। वहीं कार्यक्रम के दौरान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर (डॉ.) अजय गुप्ता एवं उप विभागाध्यक्ष डॉ. अनीता पति मिश्रा ने बताया कि सतर्कता ही साइबर अपराध से सुरक्षित रख सकती है।

दिल्ली को वैश्विक व्यापारिक केंद्र बनाने पर सीएम का जोर

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गुरुवार को 12वीं अंतरराष्ट्रीय प्लास्टइंडिया 2026 प्लास्टिक प्रदर्शनी और सम्मेलन में शामिल हुईं। विश्व स्तर के इस मंच से उन्होंने दिल्ली के औद्योगिक विकास का स्पष्ट रोडमैप साझा किया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में लगे विभिन्न स्टालों का भ्रमण किया और प्लास्टिक के विकास, रीसाइक्लिंग और सर्कुलर इकॉनमी से जुड़े इनोवेशन को नजदीक से देखा।

भारत मंडपम में आयोजित इस सम्मेलन में प्लास्टइंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष रविश कामत, प्लास्ट इंडिया 2026 की नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल (एनईसी) के चेयरमैन आलोक तिब्रेवाल, दिल्ली नगर निगम में नेता सदन प्रवेश वाही सहित 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में उद्यमी उपस्थित रहे। दिल्ली को वैश्विक शहर और मजबूत व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार उद्योग और उद्यमिता को सशक्त बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार 10 करोड़ रुपये तक का कोलेटरल-फ्री लोन उपलब्ध करा रही है ताकि छोटे उद्यमों को बिना किसी गारंटी के वित्तीय सहयोग मिल सके।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में 5,000 नए स्टार्टअप्स स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, खासकर प्लास्टिक उद्योग में इनोवेशन और सस्टेनेबल समाधानों को बढ़ावा देने के लिए। उन्होंने कहा कि 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को और बेहतर बनाने के लिए नीतियों को सरल किया जा रहा है, ताकि दिल्ली केवल कंजम्पशन हब न रहकर ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के रूप में भी अपनी पहचान बना सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्लास्टिक वेस्ट दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने में बड़ी चुनौती है और इसके समाधान के लिए रीसाइक्लिंग व वेस्ट मैनेजमेंट की आधुनिक तकनीकों पर मिलकर काम करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 2025 में भारत की प्लास्टिक इंडस्ट्री का आकार लगभग 44 अरब डॉलर रहा, जो 2026 में बढ़कर 47 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। अनुमान है कि 2030 तक यह उद्योग करीब 64 अरब डॉलर का हो सकता है। यह सेक्टर लाखों लोगों को रोजगार देता है और वैश्विक प्लास्टिक उपभोग में भारत की हिस्सेदारी लगभग 6 प्रतिशत है, जो चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत आज ग्लोबल प्लास्टिक प्रोसेसिंग हब बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान से आए सामाजिक बदलावों को याद करते हुए कहा कि प्लास्टिक निर्माण हमारा व्यवसाय हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार विकास हमारा विजन होना चाहिए। यदि प्लास्टिक को सही तरीके से

रीसाइकिल और डिस्पोज नहीं किया गया तो इसका पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 2047 के विकसित भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति से नहीं, बल्कि सोच और व्यवहार में बदलाव से हासिल होगा। एमएसएमई और 'वोकल फॉर लोकल' की भूमिका पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक उद्योग इन दोनों क्षेत्रों में अहम योगदान दे सकता है। उन्होंने कोविड-19 के दौरान पीपीई किट, मेडिकल सप्लाई और आवश्यक पैकेजिंग उपलब्ध कराने में प्लास्टिक उद्योग की भूमिका की सराहना की और कहा कि इस सेक्टर ने न केवल देश, बल्कि पूरी दुनिया की जरूरतों को पूरा कर कई जीवन बचाने में योगदान दिया। भारत को एक भरोसेमंद ग्लोबल सोर्सिंग हब बनाने में भी इस उद्योग की बड़ी भूमिका है। प्लास्टइंडिया का शुभारंभ 5 फरवरी को भारत मंडपम में हुआ और यह प्रदर्शनी 10 फरवरी तक चलेगी। भारत सरकार के रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से आयोजित यह आयोजन दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में गिना जाता है। 'भारत नेक्स्ट' थीम पर आधारित यह प्रदर्शनी आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के विजन के अनुरूप मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार सृजन और मजबूत औद्योगिक आधार को बढ़ावा देती है। इसमें 2,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शक मशीनरी, कच्चे माल, उन्नत तकनीक और सर्कुलर इकॉनमी से जुड़े समाधान पेश कर रहे हैं। खास बात यह है कि प्लास्टइंडिया 2026 को पहली बार जीरो वेस्ट एग्जिबिशन के रूप में आयोजित किया गया है, जहां कचरे का रीसाइक्लिंग और दोबारा उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है।

पुलिस ने प्रतिष्ठित ब्रांड की नकली जींस के निर्माण से जुड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया, चार गिरफ्तार

नई दिल्ली। पुलिस ने उत्तर-पश्चिम दिल्ली के लॉरेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रांड की नकली जींस बनाने और बिक्री में लिप्त गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, एक प्रतिष्ठित ब्रांड की नकली जींस, टैग और लेबल के बड़े पैमाने पर निर्माण को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी। पुलिस ने बताया कि इसके बाद सोमवार को लॉरेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र में चार स्थानों पर छापेमारी की गई और शादिक अनवर (21), रोशन झा (25), राजेश गुप्ता (43) और साजन कुमार (34) को गिरफ्तार किया गया। एक अधिकारी ने कहा, ''छापेमारी के दौरान एक टीम ने एक जाने-माने ब्रांड की 580 नकली जींस बरामद कीं। इसके अलावा, विभिन्न ब्रांड की 1,220 जींस भी जब्त की गईं।'' उन्होंने बताया कि एक अन्य परिसर से टीम ने 1,500 से अधिक जींस, एक सिलाई मशीन और शर्ट बरामद कीं। पुलिस के अनुसार, आरोपी नकली ब्रांडेड जींस और उससे जुड़े कपड़ों के निर्माण के काम में शामिल थे। वे इन कपड़ों पर नकली लेबल और टैग लगाने के बाद उन्हें असली उत्पादों के रूप में बाजार में बेचा करते थे। अधिकारी ने कहा, ''हमने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और जांच की जा रही है।

कांग्रेस ने की DTC कर्मचारी कल्याण कोष में हुए गबन की जांच की मांग

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) कर्मचारी कल्याण कोष में 22 लाख से अधिक राशि का डीटीसी के सोशल वेलफेयर विभाग के कर्मचारियों द्वारा गबन करने की जांच करने की मांग की। उन्होंने गुरुवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि कर्मचारियों के कोष से जुड़े इस मुद्दे पर दिल्ली के उप-राज्यपाल और मुख्यमंत्री स्वयं हस्तक्षेप करके दोषी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करके अपराधिक और विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि संभव हो तो उप-राज्यपाल अथवा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी सरकार के तहत डीटीसी विभाग में गड़बड़ी के इस मामले की जांच सीबीआई से भी करा सकते हैं। देवेंद्र यादव ने कहा कि लगभग 97 हजार करोड़ रुपये का घाटा झेल रही डीटीसी में कार्यरत कर्मचारियों के कल्याण कोष में 22 लाख की धोखाधड़ी होगी तो पब्लिक के लिए कर्तव्य निभाने

में कैसे मानसिक रूप से स्वस्थ्य होकर अपनी ड्यूटी कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच कराई गई तो डीटीसी में फैले संगठित भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी के बड़े नेटवर्क का खुलासा होगा। देवेंद्र यादव ने कहा कि पिछले पांच वर्षों से भी अधिक समय से डीटीसी में मुख्य सर्तकता अधिकारी (सीवीओ) का पद खाली है। डीटीसी में सीवीओ के पद को अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था के तहत विभागीय अधिकारी को नाममात्र रखा गया है, जबकि इस पर आईपीएस अधिकारी की पूर्णकालिक नियुक्ति होनी चाहिए ताकि विभाग में भ्रष्टाचार के मामलों पर रोक लगाई जा सके। देवेंद्र यादव ने कहा कि डीटीसी कर्मचारी कल्याण कोष के फंड में धोखाधड़ी करने वाले उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने दस्तावेजों को अपनी स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि डीटीसी जैसे सार्वजनिक संस्थान में लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए पारदर्शिता के साथ अधिकारियों की जवाबदेही तय करना बहुत जरूरी है।

गुमशुदा के मामलों को लेकर घबराने की जरूरत नहीं : दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने जनवरी के पहले पखवाड़े में राष्ट्रीय राजधानी में 800 से अधिक लोगों के लापता होने के आंकड़े सार्वजनिक होने के कुछ दिनों बाद बृहस्पतिवार को लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश के तहत कहा कि ''घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है'' क्योंकि ये आंकड़े वास्तव में पिछले वर्षों की इसी अवधि की तुलना में गिरावट को दर्शाते हैं। 'पीटीआई-भाषा' द्वारा प्राप्त दिल्ली पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार एक से 15 जनवरी के बीच कुल 807 लोग लापता हुए, यानी प्रतिदिन औसतन 54 लोग लापता हुए। इनमें से 509 महिलाएं और लड़कियां तथा 298 पुरुष थे।

लापता लोगों में से 191 नाबालिग और 616 वयस्क थे। पुलिस ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2026 में पिछले वर्षों की इसी अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की संख्या में कमी देखी गई। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में महीने के लिए सटीक कुल संख्या साझा नहीं की। पुलिस ने दावा किया कि वह पारदर्शी और निष्पक्ष अपराध रिपोर्टिंग नीति का पालन करती है। लापता व्यक्तियों से संबंधित सभी शिकायतों को तुरंत दर्ज किया जाता है और उनकी जांच की जाती है।

उसने कहा कि गुमशुदगी की प्राथमिकी न केवल स्थानीय पुलिस थाना में बल्कि ऑनलाइन मंच और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (112) के माध्यम से भी दर्ज की जा सकती है। बयान में कहा गया, ''गुमशुदगी के सभी मामलों में मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का सख्ती से पालन किया जाता है। गुमशुदा व्यक्ति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास शुरू किए जाते हैं, और बच्चों से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

दिल्ली की निचली अदालतों में 15.8 लाख से ज्यादा मुकदमे लंबित

नई दिल्ली। दिल्ली की निचली अदालतों में 15.8 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं, जिनमें वकील की अनुपस्थिति, अदालत द्वारा रोक लगाने और प्रक्रिया में देरी मुख्य वजहें हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के आंकड़ों से यह जानकारी मिली।

उच्चतम न्यायालय की 'ई-कमेटी' द्वारा प्रबंधित किया जाने वाला एनजेडीजी, देश भर की अदालतों में लंबित मुकदमों और निपटारे के बारे में आंकड़े देता है, जिसका मकसद पारदर्शिता बढ़ाना है। आंकड़ों से पता चलता है कि मजिस्ट्रेट मामलों का हिस्सा सबसे ज्यादा है और दिल्ली की जिला अदालतों में 10,05,813 मामले लंबित हैं। इसके बाद विभिन्न प्रकार की

2,92,670 आपराधिक शिकायतें, 96495 दीवानी वाद और सत्र अदालतों के 40,964 मामले हैं। अन्य लंबित मामलों में 20,955 विविध दीवानी मामले और 20,043 मोटर दुर्घटना दावा याचिकाएं भी शामिल हैं। कुल मिलाकर, सभी श्रेणी के लंबित मामलों की संख्या 15,85,216 है। आंकड़ों के अनुसार, देरी की वजहों में ''वकील का उपलब्ध न होना'' सबसे बड़ा कारण बनकर सामने आया, जिससे 3,27,732 मामले अटके हुए हैं। इसके बाद 2,17,905 मामले अलग-अलग कारणों से रुके हुए हैं। काफी संख्या में मामले - 26,123 - आरोपी के फरार होने के कारण भी लटके हुए हैं और 20,571 मामलों में दस्तावेजों का इंतजार हो रहा है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि गवाहों की गैर-मौजूदगी के कारण 9183 मामलों में देरी हुई है, जबकि कई अन्य मामले वादी पक्षों की दिलचस्पी की कमी, बार-बार अपील और रिकॉर्ड गायब होने के कारण लंबित हैं। एनजेडीजी के अनुसार, 590 मामलों पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाई हुई है, जबकि 42 मामलों पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई है।

दिल्ली राज्य पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के विद्यालयों में पढ़ने वाले 200 दिव्यांग छात्रों ने गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित तीसरे दिल्ली राज्य पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन 5 से 7 फरवरी तक किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम के छात्रों ने आज प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में भाग लिया। नगर निगम के छात्रों ने अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलीट विकास डागर की देख रेख में इस प्रतियोगिता में भाग लिया। दिल्ली नगर निगम के 200 दिव्यांग छात्रों ने दृष्टिबाधित,बौद्धिक अक्षमता, मस्तिष्क पक्षाघात, ड्वार्फ, लोकोमोटर हाथ एवं पैर श्रेणियों में

आयोजित 100 मीटर दौड़,लंबी कूद, गोला फेंक एवं चक्का फेंक गतिविधियों में भाग लिया। नगर निगम के दिव्यांग छात्रों ने प्रतियोगिता के पहले दिन उम्दा खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए 124 पदक जीते। निगम विद्यालयों के छात्रों का उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्शाता है कि दिल्ली नगर निगम अपने विद्यालय ने छात्रों को हर संभव सुविधाएं प्रदान कर रहा है। नगर निगम अपने विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को हर संभव सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि निगम विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें।

सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करने का आरोपी युवक गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली के द्वारका में सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करने के आरोप में 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि लड़के के कब्जे से एक पिस्तौल और एक कारतूस बरामद किया गया। ककरोला निवासी समीर को सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी के बाद 31 जनवरी को द्वारका के सेक्टर 17 से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने बताया कि उसने सोशल मीडिया मंच और 'मैसेजिंग ऐप' पर हथियार प्रदर्शित करने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए एक समर्पित टीम तैनात की है। जांच के दौरान, पुलिस को एक सोशल

मीडिया अकाउंट मिला, जहां आरोपी ने कथित तौर पर हथियार के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट की थीं और ऐसी ही तस्वीरों को 'डिस्प्ले पिक्चर' (डीपी) के रूप में इस्तेमाल किया था। पुलिस ने बताया कि तकनीकी जानकारी जुटाई गई और आरोपी को ढूंढ़ने के लिए स्थानीय सूत्रों की मदद ली गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''31 जनवरी को समीर को द्वारका के सेक्टर 17 से गिरफ्तार किया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक पिस्तौल और एक कारतूस बरामद हुआ।'' उन्होंने बताया कि शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान समीर ने बताया कि वह एक कंपनी के प्रतिनिधि (डिलीवरी बॉय) के रूप में काम करता था और उसने यह हथियार मंगोलपुरी निवासी मोनू नाम के एक व्यक्ति से अपनी सुरक्षा के लिए खरीदा था। पुलिस ने बताया कि उसने अपने इलाके के लोगों और दोस्तों के बीच खुद को 'बदमाश' के रूप में पेश करना चाहा था और अपनी छवि बनाने और प्रभाव जमाने के लिए हथियार के साथ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहा था।

महिलाओं से बदसलूकी का विरोध करने पर युवक की पिटाई

नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके में महिलाओं को परेशान कर रहे पुरुषों के एक समूह को रोकने की कोशिश करने पर युवक की पिटाई कर दी गयी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं हैं। पीड़ित की पहचान मुकेश (26) के रूप में की गयी है। सिर में गंभीर चोटें आने के कारण मुकेश अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। मुकेश की मां सर्वेश ने कहा कि तीन फरवरी की सुबह तड़के हुए हमले की क्रूरता से परिवार सदमे में है।

उन्होंने कहा, ''इन दिनों किसी की मदद करना भी एक अपराध हो गया है।'' मुकेश एक शादी से लौट रहा था जब उसने एक चाय की दुकान पर महिलाओं के एक समूह को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, जिसके परिणामस्वरूप चार पुरुषों ने उसे बुरी तरह से पीटा। मुकेश की मां

सर्वेश ने बृहस्पतिवार को 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''आज के दौर में किसी की मदद करना भी अपराध हो गया है क्योंकि मेरे बेटे ने मदद करने की कोशिश की और वह बुरी तरह घायल हो गया।'' उन्होंने कहा, ''अगर किसी ने उन्हें रोका न होता तो वे मुकेश को मार डालते। उसके पूरे शरीर पर चोटें आई हैं। उन महिलाओं और एक आदमी ने उसे बचाया और अस्पताल ले गए।'' संगम विहार निवासी मुकेश सुबह पांच बजे अपने मामा की शादी से लौट रहा था, जब वह चाय पीने के लिए रुका और उसने देखा कि कुछ लोग कथित तौर पर पास में ही दो-तीन महिलाओं को परेशान कर रहे हैं। मुकेश ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, '' मैंने उन लोगों से कहा कि ऐसा न करें। मैंने बस इतना ही कहा। इसके बाद उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया।'' मुकेश के अनुसार एक आरोपी ने पत्थर जैसी किसी वस्तु से उसके सिर पर वार किया, जिससे वह बेहोश हो गए। इसके बाद भी आरोपियों ने हमला करना जारी रखा, लेकिन एक राहगीर ने हस्तक्षेप करके स्थिति को और बिगड़ने से रोका। मुकेश ने कहा, '' एक मुस्लिम व्यक्ति ने मुझे आरोपियों से बचाया। मैं उनका बहुत आभारी हूं... अगर उन्होंने हस्तक्षेप न किया होता तो मेरी जान चली जाती।'' मुकेश ने जिन महिलाओं का बचाव किया, वे भी घटनास्थल पर ही रहीं, उन्होंने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन किया और यह सुनिश्चित किया कि वह अस्पताल पहुंच जाएं। इस घटना के संबंध में महरौली पुलिस थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच की शुरुआत महिलाओं में से एक के बयान और ऑनलाइन सामने आए हमले के वीडियो के आधार पर की गई थी। वीडियो में चार लोग एक लैंपपोस्ट के पास मुकेश पर हमला करते दिख रहे हैं। समूह में शामिल लोग मुकेश को थप्पड़ मारते, लात मारते और उसकी कमीज पकड़कर उसे गालियां देते हुए घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में विशाल रावत (26), जतिन (20), सोनू (25) और विवेक (20) नामक चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

संपादकीय

बच्चों व किशोरों को रखें सोशल मीडिया से दूर

बच्चों व किशोरों की सोशल मीडिया पर बढ़ती अति-सक्रियता अभिभावकों ही नहीं, देश के लिये भी एक गंभीर चिंता का विषय है। छात्रों का पढ़ाई से भटकाव व एकाग्रता में गिरावट समय की बड़ी फिक्र है। इसी बीच इकोनॉमिक सर्वे में सोशल मीडिया तक उम्र के हिसाब से पहुंच का सुझाव एक स्वागत योग्य कदम है। सालों से, डिजिटल विस्तार को एक बिना शर्त अच्छे बदलाव के रूप में देखा जाता रहा है। कहा जाता रहा है कि सोशल मीडिया तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने, डिजिटल लिटरेसी की खामियों को दूर करने और शिक्षा को आधुनिक बनाने में डिजिटल क्रांति सहायक है। यह स्वीकार किया जा रहा है कि बिना रोक-टोक के डिजिटल एक्सपोजर तेजी से एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बनता जा रहा है। सही मायनों में डिजिटल लत को मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षणिक प्रदर्शन और उत्पादकता को प्रभावित करने वाली समस्या के रूप मे पहचानते हुए, सर्वे इस बहस को तथ्यों पर आधारित नीति बनाने की जरूरत बताता है। इसकी सिफारिश है कि उम्र के हिसाब से एक्सेस की सीमाएं तय करने, उम्र की वेरिफिकेशन के लिये प्लेटफॉर्मों की जवाबदेही निर्धारित करने, बच्चों के लिये सरल डिवाइस बनाने और ऑनलाइन कक्षाओं पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता है। सही मायनों में इस मुद्दे पर वैश्विक सहमति का ही अनुसरण किया जा रहा है। वास्तव में बच्चों को सम्मोहित करने वाले डिजिटल डिजाइनों से उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी जरूरत है। जो कोमल मन-मस्तिष्क वाले बच्चों पर खासा नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। निश्चित रूप से डिजिटल लत के शिकार होते बच्चों व किशोरों के, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के मद्देनजर राष्ट्रीय स्तर पर नीति-निर्धारण समय की मांग है। इसके अलावा इस बाबत सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देना भी उतना ही जरूरी है। तभी इस संकट का आशाजनक समाधान तलाशना संभव हो सकेगा। वहीं दूसरी ओर, इस संकट से उबरने के लिये प्लेटफॉर्म लेवल सेफ्टी और फैमिली डेटा प्लान की भी मांग की जा रही है। जो पढ़ाई की जरूरत और मनोरंजन के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल का फर्क कर सके। इसके साथ ही हालिया आर्थिक सर्वे में इस बात को स्वीकार किया गया है कि माता-पिता पहले से ही यह जानते हैं कि व्यक्तिगत कंट्रोल बड़े पैमाने से इस समस्या का समुचित हल नहीं निकाल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए प्रयास इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। यही वजह है कि आस्ट्रेलिया व फ्रांस जैसे विकसित देशों में सरकारों को इस दिशा में सख्त पहल करनी पड़ी। यहां भी कुछ ऐसा कदम उठाने की आवश्यकता है।

ऑनलाइन गेमिंग: मनोरंजन से लत और लत से त्रासदी तक

डिजिटल युग में तकनीक जीवन को आसान बनाने का माध्यम बनी है लेकिन उसी तकनीक का अनियंत्रित उपयोग अब समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग, जो कभी मनोरंजन, एकाग्रता और रणनीतिक सोच का साधन मानी जाती थी, आज कई मामलों में बच्चों और किशोरों के लिए मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विनाश का कारण बन रही है। खासकर कोरोना काल के बाद, जब ऑनलाइन शिक्षा और घर में बंद जीवन ने बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट के और अधिक करीब कर दिया, तब से यह समस्या और गहराई है। ऑनलाइन गेम्स का मनोविज्ञान बेहद चालाकी से तैयार किया गया है। गेम डिज़ाइनर बच्चों की मानसिक संरचना को समझते हैं- इनाम, लेवल, रैंकिंग, वर्चुअल पहचान, और प्रतिस्पर्धा के ज़रिए उन्हें इस तरह बांधा जाता है कि वे बार-बार उसी दुनिया में लौटें। धीरे-धीरे खेल खेलना एक आदत बनता है, फिर ज़रूरत, और अंततः लत। यह लत शराब या नशे से कम खतरनाक नहीं होती क्योंकि इसमें शरीर नहीं, दिमाग़ जकड़ा जाता है।

- डॉ. सत्यवान सौरभ

गाजियाबाद में तीन सगी बहनों की सामूहिक आत्महत्या की खबर केवल एक अपराध समाचार नहीं है, बल्कि यह हमारे समय की सबसे भयावह सामाजिक सच्चाइयों में से एक का आईना है। नौवीं मंज़िल से कूदकर जान देने की यह घटना दिल दहला देने वाली है क्योंकि इसके पीछे कोई तात्कालिक झगड़ा, आर्थिक तंगी या पारिवारिक हिंसा नहीं बल्कि एक ऐसी अदृश्य दुनिया है, जो चुपचाप बच्चों के मन-मस्तिष्क पर कब्ज़ा कर रही है- ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सचमुच अपने बच्चों की दुनिया को समझ पा रहे हैं या हम उन्हें मोबाइल स्क्रीन के हवाले कर निश्चिंत हो बैठे हैं।

डिजिटल युग में तकनीक जीवन को आसान बनाने का माध्यम बनी है लेकिन उसी तकनीक का अनियंत्रित उपयोग अब समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग, जो कभी मनोरंजन, एकाग्रता और रणनीतिक सोच का साधन मानी जाती थी, आज कई मामलों में बच्चों और किशोरों के लिए मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विनाश का कारण बन रही है। खासकर कोरोना काल के बाद, जब ऑनलाइन शिक्षा और घर में बंद जीवन ने बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट के और अधिक करीब कर दिया, तब से यह समस्या और गहराई है। ऑनलाइन गेम्स का मनोविज्ञान बेहद चालाकी से तैयार किया गया है। गेम डिज़ाइनर बच्चों की मानसिक संरचना को समझते हैं- इनाम, लेवल, रैंकिंग, वर्चुअल पहचान, और प्रतिस्पर्धा के ज़रिए उन्हें इस तरह बांधा जाता है कि वे बार-बार उसी दुनिया में लौटें। धीरे-धीरे खेल खेलना एक आदत बनता है, फिर ज़रूरत, और अंततः लत। यह लत शराब या नशे से कम खतरनाक नहीं होती क्योंकि इसमें शरीर नहीं, दिमाग़ जकड़ा जाता है। बच्चा वास्तविक दुनिया से कटने लगता है- उसे परिवार बोझ लगने लगता है, पढ़ाई व्यर्थ लगती है और जीवन के छोटे-छोटे सुख फीके पड़ जाते हैं। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इस लत के शिकार अधिकतर बच्चे और किशोर होते हैं- वही उम्र, जब व्यक्तित्व निर्माण होता है, भावनात्मक संतुलन विकसित होता है और जीवन को समझने की प्रक्रिया चल रही होती है। इस उम्र में यदि बच्चा आभासी दुनिया में जीने लगे, तो उसकी वास्तविक समस्याओं से जूझने की क्षमता कमजोर हो जाती है। हार-जीत, तनाव, असफलता और रिश्तों की जटिलता से निपटने के बजाय वह 'एस्केप' खोजने लगता है—और ऑनलाइन गेम्स उसे यह आसान पलायन उपलब्ध कराते हैं।

गाजियाबाद की घटना में यह तथ्य और अधिक विचलित करता है कि बच्चियाँ दो साल से स्कूल नहीं जा रही थीं और मोबाइल की लत का ज़िक्र सामने आया है। यह सवाल उठता है कि क्या परिवार, स्कूल और समाज- तीनों स्तरों पर निगरानी और संवाद की कमी रही? आज के समय में बच्चों का स्कूल न जाना केवल शैक्षणिक समस्या नहीं बल्कि एक गहरी सामाजिक और मानसिक समस्या का संकेत है। स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होते बल्कि बच्चों के लिए सामाजिक संपर्क, भावनात्मक सहारा और संरचना प्रदान करते हैं। जब बच्चा इससे कट जाता है, तो वह अपने भीतर सिमटने लगता है। अक्सर अभिभावक यह मान लेते हैं कि बच्चा घर में है, मोबाइल हाथ में है, तो सुरक्षित है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। मोबाइल आज केवल संचार का साधन नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया है—जिसमें अच्छा भी है और बेहद खतरनाक भी। अभिभावकों की व्यस्तता, आर्थिक दबाव और 'डिजिटल ही भविष्य है' जैसी सोच ने बच्चों को समय से पहले एक ऐसे संसार में धकेल दिया है, जिसे वे न समझ पाते हैं और न संभाल पाते हैं। माता-पिता और बच्चों के बीच संवाद का अभाव इस खतरे को और बढ़ा देता है। यह भी एक सच्चाई है कि भारतीय समाज में मानसिक स्वास्थ्य को अब भी गंभीरता से नहीं लिया जाता। बच्चे चुप हैं, अकेले हैं, चिड़चिड़े हैं या अपने कमरे में बंद रहते हैं तो इसे 'उम्र का असर' कहकर टाल दिया जाता है। आत्मघाती विचार, अवसाद और चिंता जैसे मुद्दों पर बात करना अब भी कई परिवारों में वर्जित माना जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि समय रहते की गई एक संवेदनशील बातचीत कई जिंदगियाँ बचा सकती है। ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसके सामाजिक प्रभाव भी गंभीर हैं। अत्यधिक गेमिंग से बच्चों में हिंसक व्यवहार, आक्रामकता, सहानुभूति की कमी और सामाजिक रिश्तों से दूरी बढ़ती है। आभासी जीत उन्हें वास्तविक परिश्रम से दूर कर देती है। जब वास्तविक जीवन में चुनौतियाँ आती हैं, तो वे टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने संघर्ष करना सीखा ही नहीं होता। यही टूटन कई बार आत्मघाती कदम का कारण बनती है। यह कहना भी उचित नहीं होगा कि हर ऑनलाइन गेम या हर तकनीकी का उपयोग बुरा है। समस्या तकनीक में नहीं, उसके अनियंत्रित और गैर-जिम्मेदार उपयोग में है। यदि बच्चे सीमित समय के लिए उम्र के अनुरूप और अभिभावकों की निगरानी में गेम खेलें तो यह मनोरंजन और सीख का साधन भी हो सकता है। लेकिन जब गेमिंग जीवन का केंद्र बन जाए, तो खतरे की घंटी बज जानी चाहिए।

समाधान के स्तर पर हमें बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा। सबसे पहली जिम्मेदारी परिवार की है। अभिभावकों को बच्चों के साथ समय बिताना होगा, उनके डिजिटल व्यवहार को समझना होगा और डर या दंड की बजाय संवाद का रास्ता अपनाना होगा। मोबाइल देना आसान है, लेकिन बच्चे का मन पढ़ना कठिन—और यही कठिन काम आज सबसे ज़रूरी है। बच्चों के लिए स्पष्ट डिजिटल नियम, स्क्रीन टाइम की सीमा और वैकल्पिक गतिविधियाँ—जैसे खेल, किताबें, कला और सामाजिक मेलजोल—अनिवार्य किए जाने चाहिए। स्कूलों की भूमिका भी बेहद अहम है। केवल पाठ्यक्रम पूरा करना पर्याप्त नहीं है। डिजिटल साक्षरता, मानसिक स्वास्थ्य, और ऑनलाइन खतरों पर नियमित कक्षाएँ और परामर्श सत्र होने चाहिए। शिक्षकों को यह प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि वे बच्चों के व्यवहार में आने वाले सूक्ष्म बदलावों को पहचान सकें। स्कूल और अभिभावकों के बीच निरंतर संवाद आज की आवश्यकता है। सरकार और नीति-निर्माताओं की जिम्मेदारी भी इससे कम नहीं है। बच्चों और किशोरों के लिए ऑनलाइन गेमिंग के स्पष्ट नियम, आयु-आधारित प्रतिबंध, चेतावनी संदेश और लत पैदा करने वाले डिज़ाइन पर नियंत्रण आवश्यक है। कई देशों में 'डिजिटल वेलबीइंग' को नीति का हिस्सा बनाया गया है—भारत को भी इस दिशा में गंभीर कदम उठाने होंगे। तकनीकी कंपनियाँ केवल मुनाफ़े के बारे में न सोचें, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाएँ।

मीडिया और समाज को भी आत्ममंथन करना होगा। सनसनीखेज़ खबरों से आगे बढ़कर, हमें मूल कारणों पर चर्चा करनी होगी। ऑनलाइन गेमिंग को महज़ एक ट्रेंड या समय काटने का साधन बताकर उसके खतरों को हल्के में लेना अब संभव नहीं है। यह बच्चों के भविष्य और समाज के मानसिक स्वास्थ्य का सवाल है। गाजियाबाद की तीन बहनों की मौत हमें एक कठोर सच्चाई से रूबरू कराती है कि अगर अब भी हम नहीं चेते तो ऐसी त्रासदियाँ दोहराई जाएँगी। यह समय दोषारोपण का नहीं बल्कि जिम्मेदारी स्वीकार करने का है। परिवार, स्कूल, समाज, सरकार और तकनीकी कंपनियाँ- सभी को मिलकर बच्चों के लिए एक सुरक्षित, संतुलित और संवेदनशील डिजिटल वातावरण बनाना होगा। अंततः, हमें यह याद रखना होगा कि कोई भी गेम, कोई भी आभासी जीत, किसी बच्चे की ज़िंदगी से बड़ी नहीं हो सकती।

जाति, न्याय और लोकतंत्र : एक असहज सच्चाई

-डॉ. प्रियंका सौरभ-

भारत का लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं, बल्कि एक नैतिक संकल्प है-समानता, न्याय और बंधुत्व का। संविधान की प्रस्तावना इसी संकल्प का उद्घोष करती है। परंतु आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, तो यह प्रश्न असहज रूप से सामने खड़ा होता है कि क्या हम उस संकल्प के साथ न्याय कर पा रहे हैं? या फिर लोकतंत्र का यह ढांचा भीतर से दरक चुका है, जहाँ कानून, व्यवस्था और सत्ता-तीनों ही जाति, वर्ग और पहचान की गिरफ़्त में हैं।

आज कानून बनते हैं, संशोधन होते हैं, नए-नए प्रावधान जोड़े जाते हैं, परंतु उनके पीछे की मंशा पर सवाल उठना स्वाभाविक हो गया है। क्या ये कानून नागरिक के लिए हैं, या किसी विशेष समूह, वर्ग या वोट बैंक के लिए? जब विधायन का आधार तर्क और न्याय की जगह सामाजिक पहचान लेने लगे, तब लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ना तय है। कानून का काम समाज को जोड़ना है, लेकिन यदि वही समाज को खाँचों में बाँटने का माध्यम बन जाए, तो यह स्थिति केवल चिंताजनक नहीं, बल्कि खतरनाक भी है।

न्याय व्यवस्था की भूमिका किसी भी लोकतंत्र में सबसे पवित्र मानी जाती है। न्यायालय वह स्थान है जहाँ अंतिम उम्मीद जाकर टिकती है। लेकिन जब यह धारणा बनने लगे कि न्याय की दहलीज़ पर पहुँचने से पहले व्यक्ति की जाति, हैसियत और राजनीतिक संरक्षण देखा जा रहा है, तो विश्वास की नींव हिलने लगती है। न्याय केवल निर्णय नहीं होता; वह भरोसा होता है। और जब यह भरोसा टूटता है, तो उसका असर केवल एक व्यक्ति पर नहीं, पूरे समाज पर पड़ता है। आज न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या, फैसलों में देरी, और कुछ मामलों में दिखता स्पष्ट या अप्रत्यक्ष पक्षपात-ये सब लोकतंत्र के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रश्नचिह्न हैं। लोकतंत्र के नाम पर सत्य का क्षरण एक धीमी लेकिन निरंतर प्रक्रिया है। यह एक दिन में नहीं होता। पहले असुविधाजनक सवालों को 'राष्ट्र-विरोधी' कहा जाता है, फिर आलोचना को 'षड्यंत्र' बताया जाता है, और अंततः सच बोलने वालों को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। जब संसद में बहसें समाधान से अधिक शोर बन जाएँ, जब मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सत्ता का विस्तार बन जाए, और जब सामाजिक विमर्श भावनाओं के उकसावे तक सिमट जाए-तो समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र केवल औपचारिक रूप से जीवित है, उसकी आत्मा संकट में है।

समरसता की बातें हर मंच से होती हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई इसके उलट दिखाई देती है। समाज में विभाजन गहराता जा रहा है-धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा और क्षेत्र के नाम पर। सत्ता इन विभाजनों को पाटने के बजाय, अक्सर इन्हें साधन की तरह इस्तेमाल करती है। 'फूट डालो और राज करो' अब इतिहास की किताबों में दर्ज कोई औपनिवेशिक नीति नहीं रही, बल्कि समकालीन राजनीति की एक प्रभावी रणनीति बन चुकी है। जब जनता आपस में उलझी रहती है, तब सत्ता से सवाल करने की ताक़त कमजोर पड़ जाती है। यह विडंबना ही है कि एक ओर जाति-पाति मिटाने की बातें होती हैं, दूसरी ओर हर राजनीतिक गणित जातिगत समीकरणों पर आधारित होता है। चुनावी टिकटों से लेकर नीतिगत फैसलों तक, जाति एक निर्णायक तत्व बनी हुई है। ऐसे में 'जाति से ऊपर उठने' का उपदेश खोखला प्रतीत होता है। यदि सचमुच जाति अप्रासंगिक होती, तो उसका उल्लेख हर नीति, हर बहस और हर चुनाव में इतनी प्रमुखता से क्यों होता?

आशाओं के इस देश में निराशा का बढ़ता विस्तार केवल आर्थिक कारणों से नहीं है। बेरोज़गारी, महँगाई और संसाधनों की असमानता तो कारक हैं ही, लेकिन उससे भी बड़ा कारण है-विश्वास का टूटना। जनता ने जिन हाथों में सत्ता सौंपी, उनसे यह अपेक्षा थी कि वे सबके हित में काम करेंगे। परंतु जब वही सत्ता अपने अस्तित्व को बचाने के लिए समाज को बाँटने लगे, आलोचना से डरने लगे और असहमति को दबाने लगे, तब लोकतंत्र का नैतिक आधार कमजोर हो जाता है। सत्ता का सच से मुँह फेर लेना किसी भी समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है। जब शासन केवल अपनी छवि गढ़ने में व्यस्त हो जाए और वास्तविक समस्याओं से आँख चुराने लगे, तब झूठ एक समानांतर यथार्थ रच देता है। इस यथार्थ में आँकड़े चमकदार होते हैं, भाषण ऊँचे होते हैं, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी लगातार कठिन होती जाती है। सच को ढँकने के लिए प्रचार का सहारा लिया जाता है, और धीरे-धीरे जनता को यही सिखाया जाता है कि सवाल करना असभ्यता है। विधान सभाओं और संसद में सामाजिक न्याय की बातें अक्सर सुनाई देती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वही अन्याय नए-नए रूपों में सामने आता है। नीतियों में सुधार के नाम पर ऐसे प्रावधान लाए जाते हैं, जो या तो आधे-अधूरे होते हैं या फिर नए विवादों को जन्म देते हैं। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है, जब नीति-निर्माण में प्रभावित वर्गों की वास्तविक भागीदारी न हो, और फैसले ऊपर से थोपे जाएँ। लोकतंत्र की असली परीक्षा संकट के समय होती है। क्या वह सबसे कमजोर नागरिक के साथ खड़ा होता है, या सबसे ताकतवर के साथ? आज यह प्रश्न पहले से अधिक प्रासंगिक है। जब अन्याय किसी 'दूसरे' के साथ होता है, तब समाज का एक बड़ा हिस्सा चुप रहता है। लेकिन यही चुप्पी कल अपने ही अधिकारों के क्षरण का कारण बनती है। चयनात्मक नैतिकता-जहाँ हम केवल अपने हित का अन्याय देखते हैं-लोकतंत्र को भीतर से खोखला कर देती है। यह संपादकीय किसी एक सरकार, एक दल या एक नेता के विरुद्ध आरोप-पत्र नहीं है। यह एक सामूहिक आत्मावलोकन का आग्रह है। लोकतंत्र केवल शासकों की जिम्मेदारी नहीं, नागरिकों की भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। सवाल पूछना, असहमति जताना और सच के साथ खड़ा होना-यही लोकतंत्र की असली शक्ति है। यदि हम सुविधा के लिए चुप रहना चुनते हैं, तो फिर व्यवस्था के पतन की जिम्मेदारी से भी हम बच नहीं सकते। आज आवश्यकता है कि न्याय को फिर से उसके मूल अर्थ में लौटाया जाए-निष्पक्ष, निर्भीक और समान। कानून का उद्देश्य सत्ता को सुरक्षित करना नहीं, बल्कि नागरिक के अधिकारों की रक्षा करना होना चाहिए। राजनीति का धर्म ध्रुवीकरण नहीं, समाधान होना चाहिए। और लोकतंत्र का अर्थ केवल पाँच साल में एक बार मतदान करना नहीं, बल्कि हर दिन सजग रहना होना चाहिए। यदि हम अब भी नहीं चेते, तो आने वाली पीढ़ियाँ हमसे यह नहीं पूछेंगी कि हमने किसे वोट दिया था, बल्कि यह पूछेंगी कि जब समाज बाँटा जा रहा था, जब न्याय पहचान पूछ रहा था, और जब सच को दबाया जा रहा था-तब हमने क्या किया। यही प्रश्न आज के भारत के लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल है।

भक्तराज अंबरीश की रक्षा करता था सुदर्शन चक्र

भक्तराज अम्बरीश महाराज नागभाग के पुत्र थे। वे सप्त द्वीपवती पृथ्वी के एकमात्र सम्राट थे। संपूर्ण ऐश्वर्य के अधीश्वर होते हुए भी संसार के भोग पदार्थों में उनकी जरा भी आसक्ति नहीं थी। उनका संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में समर्पित था। जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेता है, उसके योग क्षेम का संपूर्ण भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। इसीलिये महाराज अम्बरीश की सुरक्षा के लिए भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया था। सुदर्शन चक्र गुप्त रूप से भगवान की आज्ञानुसार महाराज अम्बरीश के राजद्वार पर पहरा दिया करते थे। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी रानी के साथ भगवान श्रीकृष्ण की प्रीति के लिए वर्ष भर की एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। अंतिम एकादशी के दूसरे दिन भगवान की सविधि पूजा की गयी। ब्राम्हणों को भोजन कराया गया और उन्हें वस्त्र आभूषणों से अलंकृत गौएं दान में दी गयीं। इसके बाद राजा अम्बरीश पारण की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पधारे। अतिथिप्रेमी महाराज ने उनका अतिथि सत्कार करने के बाद उनसे भोजन करने के लिए निवेदन किया। दुर्वासाजी ने उनके निवेदन को स्वीकार किया और मध्यान्ह संध्या के लिये यमुना तट पर चले गये। द्वादशी केवल एक घड़ी मात्र शेष थी। द्वादशी में पारण न होने पर महाराज को व्रत भंग का दोष लगता, अतः उन्होंने ब्राम्हणों की आज्ञा से भगवान का चरणोदक पान कर लिया और भोजन के लिये दुर्वासा की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासाजी जब अपने नित्यकर्म से निवृत्त होकर राजमहल लौटे, तब उन्हें तपोबल से राजा के द्वारा भगवान के चरणामृत से पारण की बात अपने आप मालूम हो गयी। उन्होंने क्रोधित होकर महाराज अम्बरीश से कहा कि मूर्ख तू भक्त नहीं ढोंगी है। तूने मुझ अतिथि को निमंत्रण देकर भोजन कराने से पहले ही भोजन कर लिया है। इसीलिये मैं कृत्या के द्वारा तुझे अभी नष्ट कर देता हूं। ऐसा कहकर उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर पटका, जिससे कालाग्नि के समान एक कृत्या उत्पन्न हुई। वह भयानक कृत्या तलवार लेकर अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। उसके अम्बरीश तक पहुंचने के पूर्व ही भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसे जलाकर भस्म कर दिया।

आज का इतिहास

1715 - स्पेन और पुर्तग़ाल के बीच युद्ध समाप्त।
1716 - ब्रिटेन और हालैंड के बीच गठबंधन का नवीनीकरण।
1778 - ब्रिटेन ने फ्रांस के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया।
1788 - मैसाचुसेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को मानने वाला छठा राज्य बना।
1819 - सर थॉमस स्टैमफ़र्ड रैफ़ेल्स ने सिंगापुर की खोज की।
1833 - ओट्टो आधुनिक समय में यूनान के पहले सम्राट बने।
1869 - यूनान क्रीट छोड़ने को राजी हुआ।
1899 - स्पेन ने क्यूबा प्यूटो रिको गुआम और फिलीपींस अमरीका को सौंप दिए।
1911 - अमेरिका के एरिजोना में पहला वृद्धाश्रम खोला गया।
1918 - तीस वर्ष से अधिक की आयु की महिलाओं को ब्रिटेन में मतदान करने का अधिकार मिला।
1922 - कार्डिनल एशिले रैट्टी पोप चुने गए।
1941 - ब्रिटिश सेना ने लीबिया के बेनगाजी शहर पर क़ब्ज़ा किया।
1942 - द्वितीय विश्वयुद्धः यूनाइटेड किंगडम ने थाईलैंड के ख़िलाफ़ युद्ध की घोषणा की।
1951 - अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया।
1952 - ब्रिटेन नरेश जार्ज छठवें के निधन के बाद एलिजाबेथ द्वितीय गद्दी पर बैठीं।
1959 - सुश्री अन्ना चांडी केरल उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनीं।
1968 - फ्रांस के ग्रेनोबल शहर में दसवें शीतकालीन ओलंपिक खेल शुरु।
1985 - ब्रिटिश उपन्यासकार जेम्स हेडली चेइज का स्विट्जलैंड में निधन।
1987 - जस्टिस मैरी गॉडरन आस्ट्रेलियाई हाई कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला बनीं।
1989 - पूर्वी यूरोप में साम्यवाद को समाप्त करने की दिशा में पोलैंड में गोलमेज वार्ता की शुरुआत।
1991 - विद्रोहियों की हिंसा में 47 व्यक्तियों की मौत के बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति सीजर गैविरिया ने हिंसक गतिविधियाँ समाप्त करने की अपील की।

बेटियों के सम्मान और स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोपरि

-मनोज कुमार अग्रवाल-

मेन्स्ट्रुअल साइकल मासिक धर्म पीरियड्सकिशोर वय में कदम रखते ही बच्चियों महिलाओं की जिंदगी का अहम हिस्सा है। लेकिन इसके बावजूद इस बारे में खुलकर बातचीत करना वर्जना भरा माना जाता रहा है। आम भारतीय समाज में आज भी महिलाओं को होने वाली मासिकधर्म के बारे में न तो बात होती है और न ही इसके बारे में सोचा जाता है। शायद यही कारण है कि आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि मेन्स्ट्रुअल हेल्थ महिलाओं का मौलिक अधिकार है और हर स्कूल को फ्री सैनेटरी पैड की व्यवस्था करनी होगी।

हाल ही में यह फैसला सामाजिक कार्यकर्ता जया ठाकुर की याचिका पर आया है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि पीरियड आने पर लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, क्योंकि उनके परिवारों के पास पैड पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते। इस पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेन्स्ट्रुअल हेल्थ संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। अदालत ने आदेश दिया कि सभी स्कूलों को 6वीं से 12वीं तक पढ़ने वालीं छात्राओं के लिए फ्री सैनेटरी पैड की व्यवस्था करनी होगी। कोर्ट ने सख्त लहजे में ये भी कहा कि अगर इसका पालन नहीं होता है तो स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है।

आपको बता दें कि भारत के न्यायिक इतिहास में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो केवल कानून की व्याख्या नहीं करते, बल्कि समाज की चेतना को नई दिशा देते हैं। देश के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में लड़कियों के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना, लड़कियों लड़कों के लिए अलग वॉशरूम बनाना और डिसेबल-फ्रेंडली टॉयलेट की व्यवस्था अनिवार्य करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए है, ये फैसले इसी श्रेणी में आते हैं। शीर्ष न्यायलय ने देशभर के सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं के लिए अलग शौचालय, मुफ्त सैनिटरी पैड और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन कॉर्नर की अनिवार्यता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मासिक धर्म अब किसी हाशिए पर धकेले जाने वाला विषय नहीं, बल्कि अधिकार, स्वास्थ्य और गरिमा से जुड़ा सवाल है। अगर यह निर्णय सिर्फ सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का आदेश नहीं है, बल्कि यह लड़कियों के स्वास्थ्य, गरिमा, शिक्षा और समानता के अधिकार को संवैधानिक संरक्षण देने की ऐतिहासिक पहल है। मासिक धर्म को समाज में एक निजी, लगभग अदृश्य विषय मानकर नजरअंदाज किया जाता रहा है। स्कूलों में इसकी अनदेखी का सबसे बड़ा खामियाजा लड़कियों को भुगतना पड़ता है। सुविधाओं के अभाव में लाखों छात्राएं हर महीने कई दिन स्कूल नहीं जा पार्टी और धीरे-धीरे पढ़ाई से पूरी तरह दूर हो हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ने इस मौन पीड़ा को संविधान के दायरे में लाकर स्पष्ट कर दिया है कि यह केवल सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि मौलिक अधिकारों का प्रश्न है। अदालत का यह कहना कि मासिक धर्म स्वच्छता अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और निजता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है, भारतीय न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण विस्तार है। जीवन का अधिकार अब केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन की परिस्थितियों को भी समाहित करता है। जब एक छात्रा केवल इसलिए असहज, असुरक्षित और अपमानित महसूस करती है, क्योंकि उसके लिए बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो यह सीधे-सीधे उसके जीवन के अधिकार का हनन है। इस फैसले को एक और बड़ी विशेषता इसका शिक्षा के अधिकार से जुड़ना है। अनुच्छेद 21 के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा तभी सार्थक है जब स्कूल का वातावरण सुरक्षित, समावेशी और संवेदनशील हो। यदि मासिक धर्म के दिनों में छात्राएं स्कूल आने से मजबूरन वंचित हो जाती हैं, तो शिक्षा का अधिकार खोखला साबित होता है। अदालत ने इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए शिक्षा को केवल किताबों और पाठ्यक्रम तक सीमित न मानकर, स्वास्थ्य और गरिमा से जोड़ दिया है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी सरकारी, सहायता प्राप्स और निजी स्कूलों में मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश व्यावहारिक और दूरगामी है। यह फैसला यह भी सुनिश्चित करता है कि यह सुविधा किसी एक वर्ग या क्षेत्र तक सीमित न रहे। शहरी और ग्रामीण, सरकारी और निजी हर स्कूल इस दायित्व से बंधा होगा। इससे समानता के सिद्धांत को वास्तविक अथों में लागू करने की दिशा में कदम बढ़ता है। शौचालय सुविधाओं पर अदालत का जोर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वच्छ, कार्यशील, जैडर सेग्रिगेटेड और पानी से जुड़े शौचालय केवल बुनियादी ढांचा नहीं, बल्कि गरिमा की शर्त हैं। दिव्यांग छात्राओं के लिए अनुकूल सुविधाओं की अनिवार्यता यह दर्शाती है कि न्यायालय ने समावेशन को केंद्र में रखा है। हँडबॉश के लिए साबुन और पानी जैसी साधारण दिखने वाली चीजें भी सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, जिन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया।

जागरूकता और प्रशिक्षण पर दिया गया जोर इस निर्णय को केवल भौतिक सुविधाओं तक सीमित नहीं रहने रहने देता। जब तक छात्राएं, शिक्षक और स्कूल स्टाफ मासिक धर्म को वैज्ञानिक और स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में नहीं समझेंगे, तब तक सुविधाएं भी पूरी तरह कारगर नहीं होंगी। यह फैसला सामाजिक चुप्पी को तोड़ने का आह्वान करता है, जहां शिक्षक मदद करना चाहते हैं लेकिन संसाधनों और संवाद की कमी से बंधे रहते हैं। अदालत द्वारा अनुपालन न करने पर निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने और सरकारी स्कूलों के लिए राज्य सरकारों की जवाबदेही तय करना, इस आदेश को मजबूती देता है। अक्सर कल्याणकारी निर्देश कागजों तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन यहां सख्ती यह संदेश देती है कि यह दया या अनुग्रह का विषय नहीं, बल्कि अधिकार का प्रश्न है। सबसे मार्मिक पहलू अदालत की वह टिप्पणी है, जिसमें उसने सीधे उन लड़कियों से संवाद किया जो मासिक धर्म के कारण स्कूल से दूर रहीं और जिन्हें अशुद्ध कहकर शिक्षा से वंचित किया गया। यह कहना कि यह तुम्हारी गलती नहीं है, न्यायिक भाषा से आगे बढ़कर मानवीय संवेदना का उदाहरण है। यह संदेश केवल छात्राओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए है। यह फैसला ड्रॉपआउट दर कम करने, लैंगिक समानता बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। तीन महीने के भीतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से रिपोर्ट मांगना और केंद्र सरकार को राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश देना इस फैसले की गंभीरता को दर्शाता है। अक्सर नीतियां कागों तक सीमित रह जाती हैं, लेकिन जवाबदेही तय करने और समय-सीमा निर्धारित करने से यह उम्मीद बढ़ती है कि यह आदेश वास्तविक बदलाव में बदलेगा। मान्यता रद्द करने की चेतावनी यह भी संकेत देती है कि अब लापरवाही को बर्दास्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह सरकारी स्कूल हो या निजी। इस फैसले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि दिव्यांग-अनुकूल शौचालयों की अनिवार्यता, समावेशी शिक्षा की बात अक्सर की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर सुविधाओं की कमी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। यह निर्देश यह याद दिलाता है कि समानता का अर्थ केवल बहुसंख्यक की जरूरतें पूरी करना नहीं, बल्कि सबसे कमजोर और उपेक्षित वर्ग को केंद्र में रखना है। यह फैसला शिक्षकों और अभिभावकों के लिए भी एक आईना है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक आदित्य वशिष्ठ द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस, बी-42 सेक्टर-7 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301 से मुद्रित व बी-142/2, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 से प्रकाशित।
संपादकीय एवं संपर्क कार्यालय ए-152 सेक्टर-63, नोएडा-201301 **संपादक - आदित्य वशिष्ठ** कानूनी सलाहकार-पवित्र मोहन शर्मा आर.एन.आई. DELHIN/2012/42452
इस अंक में प्रकाशित सभी समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी होंगे। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे। e-mail: Jbttimes2021@ gmail. Com

राज्यसभा में सत्तापक्ष-विपक्ष में तीखी नोकझोंक

कांग्रेस को 'अबोध बालक' ने बनाया बंधक : जेपी नड्डा

नई दिल्ली। राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार को शुरू होते ही सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सभा की शुरुआत में जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने से रोका जा रहा है। इस पर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन की कार्यवाही में बाधा डालना नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि लोकसभा से जुड़े मामलों पर राज्यसभा में चर्चा नहीं की जा सकती।

रिजिजू ने विपक्षी सदस्यों से सदन के नियमों और परंपराओं का पालन करने की अपील की। रिजिजू ने कहा कि सदन के सभी सदस्य प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अगर कांग्रेस सदस्य उनका भाषण नहीं सुनना चाहते, तो यह उनका निर्णय है, लेकिन वे दूसरों को सुनने से नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सदन के नियमों का पालन नहीं करते।

इसके बाद सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता को यह समझना चाहिए कि लोकसभा की कार्यवाही पर राज्यसभा में चर्चा नहीं की जा सकती। इस संबंध में पूर्व सभापतियों द्वारा फैसले दिए जा चुके हैं। अगर उन्हें चर्चा करनी है तो वे अपनी पार्टी के सदस्यों से लोकसभा में इस पर चर्चा करने को कहें। मैं कांग्रेस और देश को यह संदेश देना चाहता हूं कि मोदी सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह तैयार थे, लेकिन आपने सदन को चलने नहीं दिया। आपने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बयान की मांग की थी, जिस पर पीयूष गोयल ने बयान दिया। विपक्ष के नेता ने तय समय से 20 मिनट अधिक बोला, फिर भी हमने कहा कि आप और बोल सकते हैं। लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा कहना गलत है और मैं इसकी निंदा करता हूं। एक मासूम बच्चे को बंधक बनाकर अपनी पार्टी को बंधक मत बनाइए। इस पर खरगे ने कहा कि संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। हमारे संविधान के अनुसार दो सदन हैं लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वे देशहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे। विपक्ष सदन को बाधित नहीं करना चाहता है लेकिन पिछले चार दिनों से सदन इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा। आप अपनी गलतियों को छिपाने के लिए एक सदन को पंगु नहीं बना सकते। आपने देश के साथ विश्वासघात किया है और राष्ट्र का अपमान किया है। जब राहुल इस बारे में बात करते हैं तो 'आपको खुजली उठती है'। आपकी पार्टी भी नरेन्द्र मोदी का बंधक बनी हुई है।

इस बहस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वह विपक्ष का सम्मान करती हैं लेकिन वह खरगे के भाषण से 'लिंचिंग' शब्द हटाए जाने की मांग करती हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब एक दर्जी की लिंचिंग हुई थी, लेकिन उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान एक शिक्षक का हाथ काट दिया गया था लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। करीब 40 मिनट तक यह बहस जारी रही। उसके बाद कुछ सदस्यों ने अपनी बात रखी।

पर्यटन या भ्रमण स्थल नहीं है धार्मिक स्थान : आलोक कुमार

विहिप ने किया हिंदू धार्मिक स्थलों में गैरहिंदू के प्रवेश निषेध का समर्थन

हरिद्वार। विश्व हिन्दू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने हिंदू धार्मिक स्थलों में गैरहिंदू के प्रवेश निषेध का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल पर्यटन या भ्रमण के स्थल नहीं है। उन्होंने नवरात्र में होने वाले गरबा जैसे आयोजनों में भी गैर हिंदू के प्रवेश को अमान्य किया है।

हरिद्वार प्रवास पर आए विहिप अध्यक्ष आलोक कुमार यहां गुरुवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। आलोक कुमार ने कहा कि हिन्दू समाज के धार्मिक पूजा स्थलों एवं श्रद्धा केंद्रों की अपनी प्राचीन परंपराएं, मर्यादाएं एवं धार्मिक व्यवस्था होती हैं। मंदिर पर्यटन या भ्रमण के स्थल नहीं हैं, वहां भगवान की प्रतिष्ठा होती है और श्रद्धालु पूजा-अर्चना के उद्देश्य से वहां आते हैं। जिनका धर्म मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता और मूर्ति को तोड़ने का आदेश देता हो अथवा जो मानते हो उन्हीं का भगवान, उन्हीं की पुस्तक से उन्हें मोक्ष मिलेगा, ऐसे संदर्भों में धार्मिक संस्थाएं अपनी परंपरागत व्यवस्था लागू कर सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने कहा कि नवरात्र के दौरान आयोजित गरबा केवल मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं, अपितु माता अंबा की आराधना से जुड़ी धार्मिक परंपरा है। पारंपरिक रूप से इसे नंगे पैर एवं दीपज्योति के साथ देवी की आराधना के रूप में किया जाता है। ऐसे आयोजनों की मूल धार्मिक भावना एवं परंपरा को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में अन्य धर्मों के लोगों को आने का आग्रह करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्व के विभिन्न धर्मों में भी उनके विशिष्ट धार्मिक स्थलों को लेकर विशेष परंपराएं हैं।

इस्लाम धर्म में मक्का-मदीना के पवित्र स्थलों पर गैर मुस्लिम प्रवेश प्रतिबंधित है तथा विभिन्न ईसाई संप्रदायों एवं अन्य धार्मिक परंपराओं में भी धार्मिक स्थलों के संबंध में विशेष व्यवस्थाएं प्रचलित हैं। हम यह स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह उनके विशिष्ट धर्मस्थान हैं, जहां वह श्रद्धा से पूजा करते हैं। विश्व हिन्दू परिषद का मानना है कि प्रत्येक धर्म अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार रखता है। उत्तराखण्ड की जनसंख्या संरचना के विषय पर विश्व हिन्दू परिषद की चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है।

विश्व हिन्दू परिषद मांग करती हैं कि यह अध्ययन किया जाए कि हरिद्वार एवं आसपास के क्षेत्रों में किसी विशेष समुदाय की बसावट किसी संगठित योजना के अंतर्गत तो नहीं बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विश्व हिन्दू परिषद का मानना हैं कि धार्मिक आस्था, सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए समाज एवं शासन को मिलकर संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत कार्य करना चाहिए।

केंद्र, नागालैंड सरकार और ENPO ने FNTA गठन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में गुरुवार को यहां केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) के प्रतिनिधियों के साथ नागालैंड राज्य के भीतर फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी (एफएनटीए) के गठन को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो भी उपस्थित रहे।

समझौते के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिन नॉर्थ-ईस्ट को विवाद-मुक्त, हिंसा-मुक्त और विकसित बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हर क्षेत्रीय विवाद का लोकतांत्रिक तरीके से समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने 2021-22 का जिक्र करते हुए कहा कि जब ईएनपीओ ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा की थी, तब उन्होंने संगठन से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा रखने की अपील की थी और समाधान का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने ईएनपीओ और नागालैंड सरकार के बीच सेतु की भूमिका निभाते हुए इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान निकाला है।गृह मंत्री ने कहा कि ईस्टर्न नागालैंड एक रणनीतिक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसके विकास के लिए केंद्र सरकार पूरी जिम्मेदारी निभाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि एफएनटीए के गठन, प्रशासनिक ढांचे और शुरुआती खर्चों के लिए केंद्र सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी तथा हर साल एक निश्चित राशि भी तय की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2019 के बाद से नॉर्थ-ईस्ट में 12 से अधिक महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं और मोदी सरकार की परंपरा रही है कि वह केवल समझौते ही नहीं करती, बल्कि उनके पूर्ण क्रियान्वयन के लिए भी प्रतिबद्ध रहती है।

मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि यह समझौता आपसी विश्वास को दर्शाता है और ईस्टर्न नागालैंड की आकांक्षाओं के साथ-साथ पूरे राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री ने ईस्टर्न नागालैंड के लोगों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि एक यात्रा का अंत हुआ है और विकास की नई यात्रा शुरू हो रही है। उन्होंने केंद्र सरकार के प्रति आभार जताते हुए सभी नागा जनजातियों से इसे नागा समाज की साझा जीत के रूप में देखने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार के आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि केंद्र हमें सर्वांगीण विकास की दिशा में मार्गदर्शन देता रहेगा।

भारत को हिंदुत्व पर गर्व है और हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है : मोहन यादव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हरिद्वार में संत सम्मेलन को किया संबोधित

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वैचारिक स्तर पर भारत को हिंदुत्व पर गर्व है, हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है। सनातन की धारा शाश्वत रूप से बहती रहे, इस उद्देश्य से संतवृंद और सरकार समन्वित रूप से प्रयासरत है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सनातन संस्कृति को नए आयाम तक पहुंचाने में आदि शंकराचार्य का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है।

मध्य प्रदेश की धरा से आदि शंकराचार्य का विशेष संबंध रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को हरिद्वार में समन्वय सेवा ट्रस्ट के आयोजित गुरुदेव समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना समारोह के अंतर्गत संत सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में समन्वय सेवा ट्रस्ट द्वारा स्थापित भारत माता मंदिर समाज और राष्ट्र में ऊर्जा का संचार कर रहा है।

समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. यादव का जूनापीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज ने सिंहस्थ-2028 के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। संत महात्माओं को दिया सिंहस्थ-2028 का निमंत्रण मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आदि शंकराचार्य की परंपरा के संवाहक, वैदिक सनातन संस्कृति के उन्नायक, देश के प्रथम भारत माता मंदिर के संस्थापक पद्मभूषण स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि महाराज की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भव्य और दिव्य सिंहस्थ के आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाओं और विकास कार्यों पर ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी संत महात्माओं को सिंहस्थ-2028 के लिए उज्जैन पधारने के लिए निमंत्रण दिया। समारोह में जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि संतवृंद के आशीर्वाद से देश में पिछले वर्षों में हुआ बदलाव अद्भुत है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है और तेजी से एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉटरवेज, हाई स्पीड रेल, हाईवेज से देश की युवा शक्ति और अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली है। देश की बहनें, किसान, युवा सभी समावेशी विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं। सांस्कृतिक समृद्धि, विरासत संरक्षण और धार्मिक पर्यटन में भी पूरे राष्ट्र में एक नई चेतना जागृत हुई है।

बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि संसार के दुखों का शमन केवल सत्संग से ही संभव है। हमारे प्राचीन ग्रंथ और संतों का साथ व्यक्ति को नया जीवन और दृष्टि देने में सक्षम है। संतगण वे आत्माएं हैं जिनके चरित्र शांत और उदार हैं। दूसरों का भला करने के उद्देश्य से ही संतगण की सभी गतिविधियों का संचालन होता है। भारत की पहचान सनातन से है, भारतीय संस्कृति ने मानवता का दिव्यकरण और दिव्यता का मानवीयकरण किया है। उन्होंने आदि शंकराचार्य के दर्शन पर भी अपने विचार रखें।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संत, महात्मा और धर्मगुरु सनातन चेतना के जीवंत प्रतीक हैं। उन्होंने संतवृंद का उत्तराखंड की भूमि पर स्वागत करते हुए कहा कि संत स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि महाराज ने देश की एकता और सांस्कृतिक समृद्धता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके विचार नई पीढ़ी के लिए आध्यात्मिक जागरण का आधार बनेंगे। मंचीय कार्यक्रम राष्ट्रगान जन-गण-मन के सामूहिक गान के साथ का सम्पन्न हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने योगगुरू स्वामी रामदेव के साथ किया योगाभ्यास मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार में योगगुरु स्वामी रामदेव के साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में योग आज भारत की प्राचीन परंपरा से निकलकर वैश्विक जन-आंदोलन बन चुका है। हम सभी योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ, संतुलित व ऊर्जावान जीवन की ओर कदम बढ़ाएं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पतंजलि योगपीठ के वातावरण से प्रभावित होकर कहा कि योगपीठ का संस्कार, साधना और आत्मबल से परिपूर्ण वातावरण मन को अपार शांति प्रदान करता है। उन्होंने योगगुरु स्वामी रामदेव के साथ हरिद्वार में भारत माता मंदिर में दर्शन, पूजन और यज्ञ में शामिल होकर सभी के मंगल एवं कल्याण की कामना की।

कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया

नई दिल्ली। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को फैसला किया कि वह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी नेतृत्व की पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई बैठक में यह फैसला किया गया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास '10 राजाजी मार्ग' पर हुई इस बैठक में खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शुभांकर सरकार, वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी और कई अन्य नेता शामिल हुए। कुछ नेता इस बैठक में डिजिटल माध्यम से भी जुड़े। बैठक के बाद गुलाम अहमद मीर ने संवाददाताओं से कहा कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण रणनीतिक चर्चा हुई। इसमें सभी नेताओं ने अपने सुझाव दिए हैं...पार्टी नेतृत्व ने सबकी बात सुनी और सामूहिक रूप से यह तय किया गया कि हम इस बार अकेले चुनाव लड़ेंगे।' उनका कहना था कि अलग-अलग दलों के साथ गठबंधन करने से जमीनी स्तर पर कांग्रेस का कार्यकर्ता हतोत्साहित हुआ है। मीर का कहना था कि अब कांग्रेस के पदाधिकारी इसी फैसले के मद्देनजर प्रदेश में चुनाव की तैयारी करेंगे। कांग्रेस ने वर्ष 2021 का विधानसभा चुनाव वाम दलों के साथ गठबंधन में लड़ा था और उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। पश्चिम बंगाल में आगामी अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव संभावित है।

मृत कौवों में मिला एच5एनआई संक्रमण पशुपालन विभाग ने जारी की चेतावनी

चेन्नई। तमिलनाडु राज्य में पिछले कुछ महीनों से बर्ड फ्लू का प्रकोप की स्थित चिंताजनक होता जा रही है। चेन्नई में कुछ दिनों पहले मृत मिले कौवों में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद राज्य सरकार ने पशुपालन सुरक्षा विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश ने दिए। विभाग ने सतर्क रहने की चेतावनी दी है कि यह संक्रमण मनुष्यों में भी फैलने की आशंका है।

राज्य में बर्ड फ्लू के प्रकोप के कारण राज्य का पशु चिकित्सा विभाग के दल मुर्गी फार्मों, बतख पालन केंद्रों आदि पर पशु चिकित्सा दल गहन निगरानी कार्य में लगे हैं। केरल से सटे तमिलनाडु के सीमावर्ती क्षेत्र, विशेषकर कोयंबटूर के आसपास के इलाकों में बर्ड फ्लू के प्रसार को रोकने के लिए चेक पोस्टों पर पशु चिकित्सा दल और अधिकारी तैनात किए गए हैं। केरल से तमिलनाडु आने वाले वाहनों की सख्त जांच के बाद ही उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। कोयंबटूर जिले में स्थित मुर्गी फार्मों और बतख पालन केंद्रों में यदि पक्षियों में किसी प्रकार की बीमारी या अचानक मृत्यु के मामले सामने आते हैं, तो तुरंत पशुपालन विभाग को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। बर्ड फ्लू के प्रसार को रोकने के लिए तमिलनाडु में कई स्तरों पर एहतियाती कदम उठाए जा रहे थे, लेकिन कुछ दिनों पहले चेन्नई के अडयार क्षेत्र में बड़ी संख्या में कौवों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए।

सूचना मिलने पर पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने उन कौवों के नमूने जांच के लिए भोपाल स्थित प्रयोगशाला भेजे। अब इस जांच की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मृत कौवों में एच5एनआई वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि चेन्नई क्षेत्र में बर्ड फ्लू फैल रहा है। इस संबंध में पशुपालन विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर संदिग्ध रूप से मृत पाए गए कौवों को हाथ से न छुएं। मृत कौवों को 8 से 10 फीट गहरा गड्ढा खोदकर दफनाया जाए या उन्हें जला दिया जाए।

साथ ही उस क्षेत्र में कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव किया जाए। विभाग ने बताया है कि अब तक बर्ड फ्लू से मनुष्यों में कोई संक्रमण नहीं पाया गया है, लेकिन एहतियाती कदम उठाना आवश्यक है। कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के लातूर जिले में बर्ड फ्लू के कारण बड़ी संख्या में कौवों की मौत हुई थी, जिसके चलते मृत पक्षियों वाले क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के दायरे को सुरक्षा क्षेत्र घोषित किया गया था। अब चेन्नई में फैले इस बर्ड फ्लू को लेकर भी चेतावनी दी गई है कि यह मनुष्यों में फैल सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे 'परीक्षा पे चर्चा'

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विद्यार्थियों से संवाद का कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' अपने नवें संस्करण के साथ शुक्रवार सुबह 10 बजे आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष यह कार्यक्रम पहली बार देश के विभिन्न स्थानों पर एक साथ आयोजित किया जा रहा है।

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार परीक्षा पे चर्चा 2026 का सीधा प्रसारण प्रधानमंत्री मोदी के यूट्यूब चैनल, दूरदर्शन तथा शिक्षा मंत्रालय के सोशल मीडिया मंचों पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वेव्स ओटीटी, अमेजन प्राइम वीडियो, जियो, जी फाइव, सोनी लिव और स्पॉटिफाई पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण उपलब्ध रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप परीक्षा पे चर्चा का उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है तथा परीक्षा को जीवन के एक उत्सव के रूप में देखने की भावना विकसित करना है। प्रधानमंत्री ने अपने विचारों को अपनी पुस्तक 'एग्जाम वॉरियर्स' में भी संकलित किया है, जो कई भाषाओं के साथ-साथ ब्रेल लिपि में भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित यह कार्यक्रम हर साल नए और अभिनव स्वरूप के साथ आयोजित किया जाता है। परीक्षा पे चर्चा 2026 में पहली बार दिल्ली के साथ-साथ तमिलनाडु के कोयंबटूर, छत्तीसगढ़ के रायपुर, गुजरात के देव मोगरा तथा असम के गुवाहाटी में भी आयोजन किया गया, जिससे देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य क्षेत्रों को समान रूप से शामिल किया गया है। कार्यक्रम से पूर्व देशभर के विद्यालयों में अनेक विद्यार्थी-केंद्रित गतिविधियां आयोजित की गईं।

उत्तर प्रदेश के सहकारी, एमएसएमई क्षेत्र में 2017 से बड़ा बदलाव आया: योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि 2017 से राज्य में सहकारी और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार के स्पष्ट इरादे ने जमीनी स्तर पर स्पष्ट परिणाम दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय विकास एवं रोजगार के अवसरों की कमी थी और सहकारी क्षेत्र अस्त-व्यस्त था। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले, न तो विकास था और न ही रोजगार। सहकारी क्षेत्र पर ऐसे लोग काबिज थे जो माफिया से कम नहीं थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि उस समय भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 16 जिला सहकारी बैंकों को चूककर्ता (डिफॉल्टर) घोषित किया था। उन्होंने कहा कि आज, इन 16 जिला सहकारी बैंकों में से 15 मुनाफे में आ गए हैं। बचे हुए एक को भी मुनाफे में लाने की कोशिश जारी है। यहां आयोजित आयोजित 'स्टेट क्रेडिट सेमिनार' में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) को मजबूत किया है। इस मौके पर 'स्टेट फोकस पेपर 2026-27' भी जारी किया गया। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पैक्स की संख्या बहुत अधिक है। हमने उनका 'टर्नओवर' बढ़ाया है, उनकी ऋण सीमा बढ़ाई है और उन्हें खाद वितरण के काम में शामिल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी विभाग में कर्मचारियों की कमी के बावजूद उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे अच्छे खाद वितरण प्रणालियों में से एक हासिल किया है। उन्होंने कहा कि कृषि और सहकारिता विभागों के बीच तालमेल से सहकारी समितियां एक बार फिर नए जन आंदोलन के रूप में उभरी हैं।

एमएसएमई क्षेत्र में सुधारों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पहले जो स्थिति थी उसने राज्य से बड़े पैमाने पर पलायन को मजबूर किया था। उन्होंने कहा कि कारीगर निराश थे और एमएसएमई क्षेत्र ढहने की कगार पर था। सरकार ने प्रोत्साहन दिया और 'एक जिला, एक उत्पाद' पहल के जरिये इसे बढ़ावा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश का पहला राज्य है जो अपने एमएसएमई क्षेत्र को पांच लाख रुपये तक का बीमा 'कवर' दे रहा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार की नीयत साफ होती है, तो नतीजे भी साफ दिखते हैं।

उप्र में चीनी मांझे के उपयोग पर सरकार सख्त

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हैदरगंज में चीनी मांझे से एक युवक की गर्दन कटने से हुई मौत की घटना को शासन ने गंभीरता से लेते हुए इस पर पहले से लगे प्रतिबंध को कड़ाई के साथ लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए इससे मौत होने पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने का भी आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर छापेमारी और अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला लखनऊ में एक दिन पहले हुई घटना के बाद लिया गया है। बुधवार शाम को हैदरगंज ओवरब्रिज के पास बाइक से जा रहे 33 वर्षीय मोहम्मद शोएब निवासी दुबग्गा के गले में अचानक चीनी मांझा फंसने से उनकी गर्दन की नसें कट गयीं, जिससे खून से लथपथ होकर वे बाइक समेत सड़क पर गिर पड़े और करीब 10 मिनट तक तड़पते रहे। राहगीरों ने उन्हें तुरंत ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस हादसे से इलाके में भारी आक्रोश फैल गया और लोग प्रतिबंधित मांझे की खुलेआम बिक्री पर सवाल उठाने लगे। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि मुख्यमंत्री ने इस घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने पूछा कि जब चीनी मांझे पर पहले से ही प्रतिबंध है, तो बाजार में यह कैसे उपलब्ध हो रहा है? उन्होंने साफ कहा कि अब ऐसे धागे से होने वाली किसी भी मौत को हत्या माना जाएगा और दोषियों पर उसी आधार पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि जिलेवार छापेमारी कर मांझे की बिक्री, भंडारण, सप्लाई करने वालों को पकड़ा जाए। अवैध सप्लाई चेन की पहचान कर बड़े स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसकी उच्च स्तर पर समीक्षा भी होगी।

उप्र में लापता लोगों की बढ़ती संख्या पर उच्च न्यायालय चिंतित

पुलिस के 'सुस्त' रवैये पर नाराज

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में लापता लोगों की बढ़ती संख्या का बुधवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए अदालत की रजिस्ट्री को जनहित याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया।

अदालत ने पाया कि पिछले दो सालों में एक लाख आठ लाख से ज्यादा लोग लापता हुए हैं, मगर पुलिस 'सुस्त रवैया' दिखाते हुए सिर्फ 9700 मामलों में ही कार्रवाई की है। अदालत ने हालात पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि उसके सामने रखे गए आंकड़े 'चौंकाने वाले' हैं। पीठ ने टिप्पणी की हम लापता लोगों से जुड़ी शिकायतों पर अधिकारियों के रवैये से हैरान हैं जिसमें साफ तौर पर अधिकारियों की तरफ से तुरंत कार्रवाई की ज़रूरत है।

न्यायमूर्ति अब्दुल मुईन और न्यायमूर्ति बबीता रानी की खंडपीठ ने ये टिप्पणियां विक्रमा प्रसाद की एक याचिका की सुनवाई के दौरान कीं। प्रसाद ने आरोप लगाया था कि उनका बेटा जुलाई 2024 में लापता हो गया था और पुलिस ने उसे ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। पीठ ने सुनवाई के दौरान गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव से एक विस्तृत हलफनामा मांगा। हलफनामे के अनुसार एक जनवरी 2024 और 18 जनवरी 2026 के बीच पूरे राज्य में लगभग एक लाख आठ हजार 300 लोगों की गुमशुदगी की शिकायतें दर्ज की गईं लेकिन लापता व्यक्तियों को ढूंढने के लिए सिर्फ नौ हजार 700 मामलों में ही कार्रवाई की गई।

बाकी मामलों में अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। पीठ ने इन आंकड़ों पर ध्यान देते हुए पुलिस के 'सुस्त रवैये' पर नाराजगी जताई और इस मुद्दे को व्यापक जनहित का मामला मानते हुए अदालत की रजिस्ट्री को इस मामले को एक जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले की सुनवाई पांच फरवरी को सूचीबद्ध की जाए।

बांदा की बेटी ने रचा इतिहास

इंडोनेशिया में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व

बांदा। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा के छोटे से गांव तरखरी की बेटी सार्वी पांडे ने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल कर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। एक फरवरी को गोवा में आयोजित नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सार्वी ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं।

इसके साथ ही उनका चयन इंटरनेशनल गेम्स के लिए भी हो गया है, जहां वह इंडोनेशिया में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। सार्वी के मामा आशीष दीक्षित ने गुरुवार को बताया कि 11 वर्ष की उम्र में सार्वी पांडे वर्तमान में गोवा में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और कक्षा छठवीं की छात्रा हैं। इस प्रतियोगिता में उन्होंने अंडर-16 वर्ग के अंतर्गत हिस्सा लिया और अपने से बड़े खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए दो पदक हासिल किए।

जैसे ही यह खुशखबरी गांव तरखरी पहुंची तो ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की ।

लखीमपुर में सड़क हादसे में दंपति समेत 3 की मौत, सीएम योगी ने लिया संज्ञान

लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में गोला-लखीमपुर मार्ग पर थाना गोला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तिसौरा के समीप गुरुवार अलसुबह घने कोहरे के चलते एक वैगन-आर कार को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में कार सवार दंपति समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम गोला प्रतीक्षा त्रिपाठी, तहसीलदार भीमसेन, प्रभारी गोला अंबर सिंह तत्काल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने तुरंत राहत-बचाव कार्य कराया। इसके बाद दोनों अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंभी गोला पहुंचे, जहां घायलों के उपचार की व्यवस्था की और चिकित्सकों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए।

एसडीएम गोला ने बताया कि गंभीर रूप से घायल मुकेश सिंह (25) को पहले जिला चिकित्सालय लखीमपुर खीरी और वहां से बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं परवेश सिंह (25) और तीन वर्षीय बच्ची मानवी सुरक्षित हैं। कार में कुल छह लोग सवार थे, जो सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए गए हैं। सभी दिल्ली के राजौरी गार्डन क्षेत्र में रहते थे और बहराइच जिले में आयोजित तिलक समारोह में शामिल होने जा रहे थे।

हादसे की सूचना परिजनों को दे दी गई है। इस हादसे में जिन तीन लोगों की मौत हुई है, उनमें सुनील सिंह (28) पुत्र वृंद्रा सिंह, उनकी पत्नी सुधा सिंह (26), वाहन चालक संतोष सिंह (30) पुत्र रमेश सिंह सभी निवासी ग्राम धर्मकुंडा, थाना रामगांव, जनपद बहराइच हैं।

जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह अत्यंत हृदयविदारक दुर्घटना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायलों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को पूरी मदद दी जा रही है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोला क्षेत्र में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य तेज करने और घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

चलती ट्रेन से बुजुर्ग महिला गिरी, आरपीएफ सिपाही ने बचाई जान

कानपुर। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बुधवार देर रात चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास के दौरान एक बुजुर्ग महिला यात्री गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गईं। आरपीएफ सिपाही की तत्परता से महिला को बचा लिया गया। घटना सेंट्रल स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गयी।

जनपद के मेस्टन रोड इलाके में रहने वाली बुजुर्ग महिला अनवर जहां देर रात पटना जाने के लिए कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर पांच पर पहुंची। यहां से उन्हें मगध एक्सप्रेस ट्रेन पकड़नी थी। हालांकि सेंट्रल स्टेशन पहुंचने में उन्हें कुछ देरी हो गई। जिस वजह से ट्रेन चल पड़ी। इस बीच ट्रेन में चढ़ने के दौरान उनका संतुलन बिगड़ा और वह ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच गिर गयीं। ड्यूटी पर मौजूद आरपीएफ कांस्टेबल विनोद यादव ने तत्परता दिखाते हुए समय रहते उन्हें बाहर खींच लिया। जिससे उनकी जान बच गई। घटना के बाद महिला काफी घबरा गई थी। इसलिए रेलवे पुलिस ने उनकी काउंसलिंग कराते हुए गुरुवार सुबह आठ बजे ब्रह्मपुत्र मेल से पटना के लिए रवाना कर दिया। महिला के बेटे आमिर ने बताया कि हम अपनी नानी के घर पटना जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। उधर बुजुर्ग महिला ने भी अपनी इस गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि ट्रेन में चढ़ने के दौरान किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी न करें। आरपीएफ इंस्पेक्टर एसएन पाटीदार ने बताया कि ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला का संतुलन बिगड़ गया था। जिस वजह से यह हादसा हुआ था। हालांकि समय रहते उन्हें बचा लिया गया।

फर्जी ऐप से करोड़ों की ठागी का भंडाफोड़ दो अंतरराज्यीय साइबर अपराधी गिरफ्तार

आजमगढ़। जिले के साइबर थाना पुलिस ने नेक्स्ट स ट्रेड नाम की एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप से की जा रही करोड़ों की ऑनलाइन ठगी का भंडाफोड़ करते हुए उज्जैन-इंदौर से जुड़े दो अंतरराज्यीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

जांच में करीब एक करोड़ रुपये की ठगी और बैंक कर्मियों की संलिप्तता सामने आई है। गुरुवार को पुलिस लाइन सभागार में ठगी का खुलासा करते हुए नोडल अधिकारी साइबर क्राइम विवेक त्रिपाठी ने बताया कि बदरका निवासी पीड़ित अशोक कुमार अग्रवाल ने फेसबुक विज्ञापन देखकर उन्होंने नेक्स्ट ट्रेड ऐप डाउनलोड किया।

उन्होंने उसमें 8.99 लाख रुपये निवेश किए। शुरुआत में मुनाफा दिखाया गया, लेकिन निकासी के प्रयास पर आईडी ब्लॉक कर दी गई। तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने तीन फरवरी को इन्द्रजीत डे निवासी ईस्ट दिल्ली, वर्तमान पता उज्जैन तथा अंकेश धाकड़ निवासी शिवपुरी, वर्तमान पता इंदौर के रूप में हुई है। अंकेश धाकड़ कोटक महिंद्रा बैंक इंदौर में कार्यरत था, को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से तीन मोबाइल, तीन एटीएम कार्ड, दो चेक बुक, बैंक आईडी, जियो सिम और 870 नकद बरामद हुए हैं।

पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह गिरोह म्यूल खातों के जरिए पैसा ट्रांसफर कराता था। जांच में गोपाल भदौरिया (कोटक बैंक कर्मी), माधव, रॉकी और प्रीतम (यस बैंक कर्मी) फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। ये सभी ब्लैंक चेक उपलब्ध कराते थे।

अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, नहर में पाया गया शव

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित करछना थाना क्षेत्र में बुधवार रात गढ़ैला गांव के पास किसी वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नहर में गिर गया और उसकी मौत हो गई। गुरुवार सुबह खोजते हुए परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो शव नहर में पाया। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई की। करछना सहायक पुलिस आयुक्त सुनील कुमार ने बताया कि हादसे में प्रयागराज जिले के हंडिया थाना क्षेत्र के दुमदुमा गांव निवासी राजेंद्र निषाद (50) पुत्र खेमराज निषाद की मौत हुई है। पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि वह अपनी बेटी को मोटरसाइकिल से नैनी छोड़ने के लिए गया था। बेटी को छोड़कर अपनी बहन के घर जाने के लिए बुधवार रात जा रहा था। लेकिन रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। जब फोन से सम्पर्क नहीं हुआ तो रिश्तेदारों से पता किया और खोजते हुए गुरुवार को परिजन घटनास्थल पर पहुंचे ।

एंबुलेंस ने सड़क पार कर रही बच्ची को कुचला, मौत

औरैया। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में दिबियापुर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम चिचोली में गुरुवार को तेज रफ्तार एंबुलेंस ने सड़क पार कर रही मासूम बच्ची को रौंद दिया। हादसे में उसकी मौत हो गई और इस घटना से नाराज परिजनों ने सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा देकर परिवार को शांत कराया हैं।

सदर कोतवाल राजकुमार ने बताया कि ग्राम चिचोली निवासी जयचंद्र यादव की पांच साल की पुत्री रिया सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान तेज गति से आ रही एंबुलेंस ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बच्ची उछलकर एंबुलेंस के पिछले पहिए के नीचे आ गई और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद लोगों ने एंबुलेंस को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक वाहन को मौके से तेज रफ्तार में भगा ले गया। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंच गए और सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर सदर कोतवाल राजकुमार सिंह पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित परिजनों को समझाने का प्रयास किया। परिजनों का आरोप है कि एंबुलेंस चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने परिवार को आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन देते हुए फरार एंबुलेंस चालक की तलाश शुरु कर दी।

निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं: डीएम

सीतापुर। जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर. ने गुरुवार को आदर्श तहसील महोली परिसर में निर्माणाधीन उप निबंधक कार्यालय भवन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को गंभीरता से परखते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि, सरकारी भवनों में घटिया सामग्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि पिलर निर्माण के बाद कहीं भी सरिया दिखाई नहीं देना चाहिए, यह सुनिश्चित किया जाए। निर्माण कार्यों में बेहतर गुणवत्ता वाली सामग्री का ही उपयोग और मानकों का पूर्णतः पालन किया जाए। भवन के भीतर बनाए जा रहे शौचालयों का भी निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने पर्यटन विभाग के जरिए विकास खंड ऐलिया के ग्राम रोजहा (पोस्ट धौरेमऊ) स्थित प्राचीन शिव मंदिर में कराए जा रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का जायजा लिया। इंटरलॉकिंग, सोलर लाइट एवं अन्य विकास कार्यों को देखते हुए प्रकाश व्यवस्था संतोषजनक न मिलने पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।

चंद्रशेखर आज़ाद बलिदान दिवस समारोह 27 फरवरी को लोहिया खुर्द में, तैयारियों को लेकर बनी रणनीति

औरैया। उत्तर प्रदेश केऔरैया जिले में चंबल संग्रहालय, पंचनद द्वारा अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान दिवस के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन आगामी 27 फरवरी को लाल सेना स्मारक, लोहिया खुर्द में किया जाएगा।

समारोह की तैयारियों को लेकर गुरुवार को आयोजित बैठक में रूपरेखा तय की गई और जनसंपर्क अभियान तेज करने का निर्णय लिया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद का चंबल अंचल से गहरा और ऐतिहासिक नाता रहा है। स्वतंत्रता संग्राम को गति देने के लिए उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ इसी अंचल में कई गुप्त बैठकों के माध्यम से फिरंगी हुकूमत को उखाड़ फेंकने की रणनीति तैयार की थी। चंबल संग्रहालय स्मरण दिवस के माध्यम से भारत माता की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने वाले अमर क्रांतिकारी के विचारों को निरंतर याद करता रहा है। बैठक को संबोधित करते हुए चंबल संग्रहालय के निदेशक चन्द्रोदय सिंह चौहान ने कहा कि अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के क्रांतिकारी विचारों से नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए सतत प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने बलिदान दिवस समारोह की विस्तृत रूपरेखा पर चर्चा की।

वहीं क्रांतिकारी लेखक डॉ. शाह आलम राणा ने सभी से बलिदान दिवस समारोह को ऐतिहासिक बनाने की अपील की।

आयोजन समिति से जुड़े डीके सिकरवार ने जानकारी दी कि अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बलिदान दिवस के अवसर पर लाल सेना स्मारक, लोहिया खुर्द में प्रातः 10 बजे से वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए दर्जनों टीमों से संपर्क किया गया है। बैठक में आयोजन समिति से जुड़े चन्द्रवीर चौहान, डॉ. ज्योति यादव, बलवीर शांखवार, सत्यम प्रजापति, श्रीमती क्षमा चौहान, विकास बाथम, आसिव कुमार, राज शंखवार, राम प्रताप सिंह चौहान, राजवीर सिंह यादव, जयेंद्र चौहान सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

अंडर 19 विश्व कप : जॉर्ज, आयुष म्हात्रे के शानदार फॉर्म के दम पर भारत का पलड़ा इंग्लैंड पर भारी

हरारे। छठा खिताब जीतने की कोशिश में जुटी भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम जब आईसीसी अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में शुक्रवार को इंग्लैंड से खेलेगी तो उसकी उम्मीदें शानदार फॉर्म में चल रहे अपने बल्लेबाजों पर टिकी होंगी। अफगानिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने जीत दर्ज की जिसमें कप्तान आयुष म्हात्रे और सलामी बल्लेबाज आरोन जॉर्ज ने यादगार पारियां खेली। इस जीत से पांच बार की चैम्पियन भारतीय टीम का हौसला बढा है जिसने पिछली बार 2022 में खिताब जीता था।

भारत ने अमेरिका के खिलाफ पहले ग्रुप मैच से ही बेहतरीन खेल दिखाया है। सेमीफाइनल में 300 से अधिक के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान को हराकर भारतीय टीम ने अपराजेय रिकॉर्ड कायम रखा। अब उसका सामना एक और अपराजेय टीम इंग्लैंड से होना है। भारत को बखूबी पता है कि गत चैम्पियन आस्ट्रेलिया को हराकर इंग्लैंड के हौसले बुलंद है और उसे हराना आसान नहीं होगा। भारत को एक ईकाई के रूप में अच्छा प्रदर्शन करना होगा और नजरें वैभव सूर्यवंशी पर भी लगी होंगी जिनके बल्ले से हो रही आतिशबाजी का जवाब तलाशने के लिये विरोधी गेंदबाज जूझते नजर आये हैं।अगले महीने 15 वर्ष के हो रहे सूर्यवंशी तीन अर्धशतक और एक शतक लगा चुके हैं। इंग्लैंड के सामने उन्हें हालांकि संयम से खेलना होगा क्योंकि मैन्नी लुम्सडेन की अगुवाई में उसके पास मजबूत तेज गेंदबाजी आक्रमण है।

भारत का अंडर 19 विश्व कप फाइनल में रिकॉर्ड अच्छा रहा है और दसवीं बार टीम फाइनल में पहुंची है। पिछली बार 2022 में वेस्टइंडीज में हुए टूर्नामेंट में भारत ने इंग्लैंड को ही हराया था। अफगानिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में म्हात्रे के फॉर्म में लौटने से बल्लेबाजी और मजबूत हुई है। मध्यक्रम में विहान मल्होत्रा ने कई अच्छी पारियां खेली हैं जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू भी दो अर्धशतक लगा चुके हैं। दीपेश देवेंद्रन , हेनिल पटेल और आर एस अम्बरीश की मौजूदगी में भारतीय तेज आक्रमण भी अच्छा रहा है लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज तेज गेंदबाजों को खेलने में माहिर हैं। ऐसे में स्पिनर कनिष्क चौहान और खिलन पटेल की भूमिका अहम हो जायेगा हालांकि टीम संयोजन पिच की स्थिति पर निर्भर करेगा। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले शीर्ष पांच गेंदबाजों में कोई भारतीय नहीं है। इंग्लैंड के मैन्नी लुम्सडेन 15 विकेट लेकर शीर्ष पर है। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने एक ईकाई के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया है।

इंग्लैंड के लिये बेन मायेस ने एक शतक और दो अर्धशतक समेत 399 रन बनाये हैं। कप्तान थॉमस रियू भी अच्छे फॉर्म में हैं और सेमीफाइनल में आस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक समेत 299 रन बना चुके हैं।

दोनों टीमें इस प्रकार हैं।

भारतः आरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, हरवंश पंगालिया, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, दीपेश देवेंद्रन, हेनिल पटेल, मोहम्मद एनान, उद्धव मोहन और किशन सिंह।

इंग्लैंड : थॉमस रियू (कप्तान), राल्फी अलबर्ट, अली फारूक, बेन डॉकिंस, कालेब फाकनेर, फरहान अहमद, एलेक्स फ्रेंच, एलेक्स ग्रीन, ल्यूक हैंड्स, इसाक मोहम्मद, मैन्नी लुम्सडेन, बेन मायेस, जेम्स मिंटो, जोसेफ मूरेस, सेबेस्टियन मोर्गन

मैच का समय : दोपहर एक बजे से।

मैनचेस्टर सिटी काराबाओ कप के फाइनल में
आर्सेनल से होगी खिताबी जंग

मैनचेस्टर। मैनचेस्टर सिटी ने बुधवार रात काराबाओ कप (लीग कप) के सेमीफाइनल में न्यूकैसल को 3–1 से हराकर कुल 5–1 के एग्रीगेट स्कोर के साथ फाइनल में जगह बना ली। अब फाइनल मुकाबले में प्रीमियर लीग की शीर्ष दो टीमें आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी- 22 मार्च को वेम्बली स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। इस मुकाबले में सिटी के फॉरवर्ड ओमर मारमूश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो गोल दागे, जबकि एक गोल तिजानी रेंडर्स ने किया। पहले लेग में 2–0 की बढ़त लेने वाली सिटी ने घरेलू मैदान एतिहाद स्टेडियम में सेमीफाइनल को लगभग एकतरफा बना दिया। न्यूकैसल की ओर से सांत्वना गोल सब्स्टीट्यूट एंथनी एलांगा ने किया। मारमूश ने मैच के सातवें मिनट में सिटी को बढ़त दिलाई, जब डैन बर्न के टैकल से गेंद उनके शरीर से टकराकर गोल में चली गई। 29वें मिनट में कीरन ट्रिपियर की खराब क्लीयरेंस पर मारमूश ने हेडर से अपना दूसरा गोल किया। इसके तीन मिनट बाद रेंडर्स ने बॉक्स के अंदर से जोरदार शॉट लगाकर स्कोर 3–0 कर दिया। 62वें मिनट में एलांगा ने न्यूकैसल के लिए गोल किया, जिससे स्कोरलाइन थोड़ी सम्मानजनक हो सकी। मैच के बाद मारमूश ने स्काई स्पोर्ट्स से बातचीत में कहा, "हम ट्रॉफी जीतने के लिए खेलते हैं और हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं ताकि फाइनल तक पहुंचें और सिल्वरवेयर उठा सकें।" वहीं सिटी के मैनेजर पेप गार्डियोला ने आर्सेनल की तारीफ करते हुए कहा, "आर्सेनल इस समय शायद यूरोप ही नहीं, दुनिया की भी सबसे बेहतरीन टीम है। उनके खिलाफ खेलना हमें और बेहतर बनाएगा।" आर्सेनल ने मंगलवार को चेल्सी को 1–0 से हराकर कुल 4–2 के एग्रीगेट के साथ फाइनल में प्रवेश किया था। प्रीमियर लीग में आर्सेनल फिलहाल छह अंकों की बढ़त के साथ शीर्ष पर है, जबकि सिटी दूसरे स्थान पर है। दोनों टीमें चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 और एफए कप के चौथे दौर में भी पहुंच चुकी हैं। यह फाइनल दोनों क्लबों के बीच हालिया प्रतिद्वंद्विता को और धार देगा। सिटी ने 2023 और 2024 में आर्सेनल को पीछे छोड़ते हुए लीग खिताब जीता था।

हॉकी इंडिया ने एफआईएच पुरूष प्रो लीग के लिये 24 सदस्यीय टीम का ऐलान किया

नई दिल्ली। हॉकी इंडिया ने राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में दस से 15 फरवरी तक होने वाले एफआईएच प्रो लीग के पहले चरण के लिये 24 सदस्यीय भारतीय पुरूष टीम की घोषणा की। हॉकी इंडिया ने पिछले महीने 33 संभावित खिलाड़ियों की सूची जारी की थी जिसे अब घटाकर 24 कर दिया गया है। इस चरण में भारत के अलावा बेल्जियम और अर्जेंटीना की टीमें भाग लेंगी। भारत के मुख्य कोच क्रेग फुल्टोन ने एक विज्ञप्ति में कहा ,'' टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है। हमारे पास रोशन कुजूर और मनमीत सिंह जैसे युवा हैं जबकि सीनियर खिलाड़ी भी टीम में हैं। यह संतुलन काफी जरूरी है। अर्जेंटीना और बेल्जियम बेहतरीन टीमें हैं और हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने उतरेंगे।'' पिछले सत्र में नौ टीमों में आठवें स्थान पर रही भारतीय टीम पहला मैच 11 फरवरी को बेल्जियम के खिलाफ खेलेगी जबकि 13 फरवरी को अर्जेंटीना से खेलना है। इसके बाद 14 फरवरी को बेल्जियम से और 15 फरवरी को अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। इसके बाद भारतीय टीम होबर्ट जायेगी जहां 21 और 24 फरवरी को स्पेन से और 22 तथा 25 फरवरी को आस्ट्रेलिया से खेलना है। लीग का यूरोपीय चरण जून में खेला जायेगा।

भारतीय टीम :

गोलकीपर : सूरज करकेरा, पवन

डिफेंडर : अमित रोहिदास, जरमनप्रीत सिंह, जुगराज सिंह, हरमनप्रीत सिंह, सुमित, संजय, नीलम संजीप सेस, अमनदीप लाकड़ा

मिडफील्डर : राजिंदर सिंह, मनमीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद, हार्दिक सिंह, एम रबिचंद्र सिंह, नीलाकांता शर्मा, रोशन कुजूर

फॉरवर्ड : अभिषेक, सुखजीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सेल्वम कार्ति, मनदीप सिंह, अराइजीत सिंह हुंडल, आदित्य अर्जुन लालागे

भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार का फैसला सही, हम बांग्लादेश के साथ : पाक प्रधानमंत्री

कराची। भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप के मैच के बहिष्कार को सही फैसला बताते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने कहा कि बांग्लादेश के समर्थन के लिये यह 'सोच समझकर' लिया गया फैसला है। पाकिस्तान सरकार ने अपनी क्रिकेट टीम को कोलंबो में भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाला मैच नहीं खेलने के लिये कहा है। इससे पहले सुरक्षा कारणों से भारत में खेलने से इनकार पर बांग्लादेश को विश्व कप से हटाकर स्कॉटलैंड को उसकी जगह शामिल किया गया। शरीफ ने यहां सरकार की एक बैठक के बाद कहा ,'' हमने टी20 विश्व कप पर स्पष्ट रूख अपनाया है कि हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे क्योंकि खेल के मैदान पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिये।'' उन्होंने कहा ,' हमने सोच समझकर यह रूख अपनाया है और हम पूरी तरह से बांग्लादेश के साथ हैं। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही फैसला है।'' जवाब में बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरूल ने जवाब में अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर लिखा ,'' शुक्रिया पाकिस्तान।'' आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चेताया है कि यह 'हाई प्रोफाइल' मैच नहीं खेलने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। प्रसारकों, प्रायोजकों और विज्ञापनदाताओं के लिये यह मैच कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। पाकिस्तानी टीम बाकी लीग मैच खेलने कोलंबो पहुंच गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह चुका है कि भारत का सामना अगर नॉकआउट चरण में होता है तो वह सरकार की सलाह पर अमल करेगा। पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने कहा था कि बांग्लादेश को बाहर करने का फैसला सही नहीं है और सुरक्षा चिंताओं का निवारण किया जाना चाहिये था। आईसीसी ने भारत में विश्व कप मैचों के आयोजन स्थलों का सुरक्षा दौरा करके बांग्लादेश के लिये जोखिम को कम से मध्यम श्रेणी में रखा था। तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को बीसीसीआई के निर्देश पर आईपीएल से बाहर किये जाने के बाद बांग्लादेश ने भारत में खेलने से इनकार कर दिया था। भारतीय बोर्ड ने कारण नहीं बताया लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बीच यह फैसला लिया गया।

कारोबार

संक्षिप्त खबरें

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा आज करेंगे मौद्रिक समीक्षा का ऐलान

मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा 6 फरवरी को सुबह 10 बजे तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के फैसले का ऐलान करेंगे। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार आरबीआई एमपीसी की बैठक में पॉलिसी दरों रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा। आरबीआई ने गुरुवार को 'एक्स' पोस्ट पर बताया कि रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा 2026 की पहली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 4 से 6 फरवरी तक चलने वाली मौद्रिक समीक्षा बैठक की लाइव टेलीकास्ट बयान सुबह 10:00 बजे से देंगे। लाइव ब्रॉडकास्ट https://youtube.com/live/mdKWN13DZTw?feature=share पर देखें और पॉलिसी के बाद प्रेस कांफ्रेंस दोपहर 12:00 बजे होगी। इसका लाइव लिंक https://youtube.com/live/zATfxVdxXG0?feature=share पर आप देख सकते हैं। उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने फरवरी, 2025 से लेकर अबतक नीतिगत ब्याज दर रेपो रेट में कुल 125 फीसदी तक की कटौती कर चुका है, जिससे रेपो रेट घटकर 5.25 फीसदी पर आ गया है। जानकारों का कहना है कि महंगाई अब अपने निचले स्तर से दोबारा ऊपर आने लगी है, इसलिए केंद्रीय बैंक और जोखिम लेने से बचेगा और इस बार रेपो रेट को यथावत रखेगा।

सन फार्मा 500 करोड़ रुपये के निवेश से असम में विनिर्माण इकाई करेगी स्थापित

गुवाहाटी। अग्रणी दवा कंपनी सन फार्मास्युटिकल असम में एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इससे 500 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। मुख्य सचिव रवि कोटा ने यह जानकारी दी। दवा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को मुख्य सचिव के साथ बैठक में परियोजना के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की थी। कोटा ने बुधवार देर रात सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा,'' सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और असम में औषधि विनिर्माण इकाई स्थापित करने के कंपनी के प्रस्ताव की समीक्षा की।'' कंपनी की ओर से वरिष्ठ उपाध्यक्ष राहुल अवस्थी और कार्यकारी उपाध्यक्ष रंजीत मोहापात्रा ने कोटा से मुलाकात की। मुख्य सचिव ने कहा, '' प्रस्ताव में राज्य में दवा फॉर्मुलेशन विनिर्माण इकाइयों की स्थापना शामिल है, जो भारतीय बाजार की जरूरतों को पूरा करेंगी। इस परियोजना में 500 करोड़ रुपये से अधिक का नियोजित निवेश दो चरणों में किया जाएगा।'' उन्होंने कहा कि परिचालन शुरू होने के बाद चरणबद्ध तरीके से इस परियोजना से 500 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है।

यूरोप के बाद खाड़ी देशों के साथ व्यापार समझौता करेगा भारत

भारत, खाड़ी सहयोग परिषद ने एफटीए पर बातचीत शुरू करने के लिए नियम-शर्तों पर किए हस्ताक्षर

नई दिल्ली। भारत और पश्चिमी एशियाई देशों के समूह खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने के लिए नियम एवं शर्तों पर बृहस्पतिवार को हस्ताक्षर कर दिए। नियम एवं शर्तों में प्रस्तावित व्यापार समझौते का दायरा और तौर-तरीके बताए गए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जीसीसी के साथ बातचीत को लेकर नियम एवं शर्तों पर हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता की। जीसीसी, खाड़ी क्षेत्र के छह देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन का समूह है। गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि करीब एक करोड़ भारतीय जीसीसी क्षेत्र में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता मई, 2022 में पहले ही लागू कर दिया था। भारत और ओमान ने 18 दिसंबर, 2025 को मस्कट में एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए थे। जीसीसी के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर एक तरह से बातचीत फिर से शुरू हो रही है। इससे पहले दो दौर की बातचीत 2006 और 2008 में में हुई थी। जीसीसी द्वारा सभी देशों और आर्थिक समूहों के साथ वार्ता स्थगित करने के कारण तीसरे दौर की वार्ता नहीं हो पाई थी। भारत मुख्य रूप से सऊदी अरब तथा कतर जैसे खाड़ी देशों से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस आयात करता है और इन देशों को मोती, कीमती एवं अर्ध-कीमती पत्थर, धातु, विद्युत मशीनरी, लोहा व इस्पात तथा रसायन निर्यात करता है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का जीसीसी देशों को निर्यात सालाना आधार पर लगभग एक प्रतिशत बढ़कर लगभग 57 अरब अमेरिकी डॉलर रहा जो एक साल पहले 2023-24 में 56.32 अरब अमेरिकी डॉलर था। वहीं आयात 2024-25 में 15.33 प्रतिशत बढ़कर 121.7 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 161.82 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 178.7 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। संयुक्त अरब अमीरात गत वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। इस सूची में सऊदी अरब पांचवें, कतर 22वें, ओमान 28वें, कुवैत 29वें और बहरीन 65वें स्थान पर रहा।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील का जॉइंट स्टेटमेंट 4-5 दिन में आएगा: गोयल

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अगले चार से पांच दिनों में संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि संयुक्त बयान के बाद एक औपचारिक समझौता होगा, जिस पर मार्च के बीच में हस्ताक्षर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि संयुक्त बयान के बाद अमेरिका मौजूदा टैरिफ को 18 फीसदी तक कम करने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी करेगा। अमेरिका-भारत व्यापार समझौते पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग ने यहां एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते का पहला हिस्सा लगभग तैयार है। पीयूष गोयल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले 4-5 दिनों में एक संयुक्त बयान (जॉइंट स्टेटमेंट) पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। गोयल ने संवाददाताओं को बताया कि समझौते के पहले चरण के लिए कानूनी समझौते पर मार्च के मध्य तक हस्ताक्षर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त बयान के बाद एक विस्तृत कानूनी समझौता किया जाएगा। वाणिज्य मंत्री ने साथ ही बताया कि इस समझौते में किसी भी प्रकार के निवेश की प्रतिबद्धता नहीं है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि एक बार बयान पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद यह एक कानूनी समझौते में तब्दील हो जाएगा, जबकि मार्च के मध्य तक हमें उस कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क में कटौती करेगा।

भारत-अमेरिका ऊर्जा गलियारा वार्ता में भारत की वृद्धि-आधारित ऊर्जा प्राथमिकताओं पर जोर

ह्यूस्टन। कौंसुल जनरल डी सी मंजुनाथ ने कहा कि भारत की तेज आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने की महत्वाकांक्षा दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा से गहराई से जुड़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि भरोसेमंद एवं किफायती ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ स्वच्छ प्रौद्योगिकियों तथा नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी उद्योग के साथ संवाद और सहयोग बेहद अहम है। ह्यूस्टन स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास (सीजीआई) ने यहां अपने कार्यालय में अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच (यूएसआईएसपीएफ) के सहयोग से 'ग्लोबल एनर्जी आउटलुक' 2026 पर चार फरवरी को एक उच्चस्तरीय अमेरिका-भारत ऊर्जा गोलमेज बैठक आयोजित की। इस बैठक में वैश्विक ऊर्जा, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी कंपनियों के 30 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इनमें एक्सॉनमोबिल, शेवरॉन, हनीवेल, गेल, लार्सन एंड टुब्रो, वेदरफोर्ड, लैंजाटेक, एसएंडपी ग्लोबल, मैकिन्से और सोसाइटी ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियर्स के प्रतिनिधि शामिल थे। भारत के महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि यह गोलमेज बैठक साझा ऊर्जा चुनौतियों और व्यावसायिक अवसरों पर नीति निर्माताओं तथा उद्योग जगत के लोगों के बीच संवाद के लिए मंच उपलब्ध कराने के उसके निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। यह गोलमेज बैठक फरवरी 2026 के भारत-अमेरिका व्यापार ढांचे पर सहमति बनने के बाद हुई। इसमें ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी सहयोग को द्विपक्षीय वृद्धि के प्रमुख कारक के रूप में चिह्नित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि लांजा टेक तथा हनीवेल जैसी कंपनियों की भागीदारी भारत के औद्योगिक और विमानन क्षेत्रों से जुड़ी सतत विमानन ईंधन एवं कार्बन पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों में बढ़ती व्यावसायिक रुचि को दर्शाती है। यूएसआईएसपीएफ के अनुसार, चर्चाएं वैश्विक आपूर्ति-मांग रुझानों, अवसंरचना निवेश और नीतिगत ढांचों पर केंद्रित रहीं जो अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों और भारतीय सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच गहरे व्यावसायिक जुड़ाव को संभव बना सकती हैं। एक्सॉनमोबिल में अर्थशास्त्र एवं ऊर्जा के कॉरपोरेट निदेशक प्रसन्ना वी. जोशी द्वारा प्रस्तुत 'ग्लोबल एनर्जी आउटलुक' में आने वाले दशकों में भारत की ऊर्जा मांग में निरंतर वृद्धि के अनुमान पेश किए गए जो औद्योगिक विस्तार, शहरीकरण और बढ़ती बिजली खपत से प्रेरित होगी। प्रतिभागियों ने कहा कि भारत की निकट-अवधि की प्राथमिकताओं में एलएनजी और प्राकृतिक गैस अवसंरचना का विस्तार, बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाना तथा उद्योग और डेटा सेंटर से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में डिजिटल एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों की तैनाती शामिल है।

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस ने एक करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए

वित्त वर्ष 2026-27 में एक करोड़ और लगाएगी

नई दिल्ली। अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) एक करोड़ स्मार्ट बिजली मीटर लगाने वाली भारत और संभवतः दुनिया की भी पहली कंपनी बन गई है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को बयान में यह दावा किया और कहा कि अगले वित्त वर्ष 2026-27 में भी एक करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड को पांच राज्यों में कुल 2.5 करोड़ स्मार्ट बिजली मीटर लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंपनी का दावा है कि रोजाना 25 हजार स्मार्ट मीटर लगाने की उसकी गति उद्योग में सबसे तेज है। यह उपलब्धि कंपनी के तय लक्ष्य से काफी पहले हासिल हुई है। कंपनी ने 31 मार्च 2026 तक एक करोड़ मीटर लगाने का लक्ष्य रखा था। एईएसएल का स्मार्ट मीटर नेटवर्क उपभोक्ताओं को वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करता है, बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ाता है और विद्युत वितरण संचालन को मजबूत बनाता है। एईएसएल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कंदर्प पटेल ने कहा, '' एक करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने की यह उपलब्धि हमारे उच्च स्तरीय कार्यान्वयन कौशल और वितरण कंपनियों एवं उपभोक्ताओं के साथ गहरे सहयोग का प्रमाण है।''

'मिर्जापुरः द मूवी' की रिलीज डेट का ऐलान
चार सितंबर को बड़े पर्दे पर देगी दस्तक

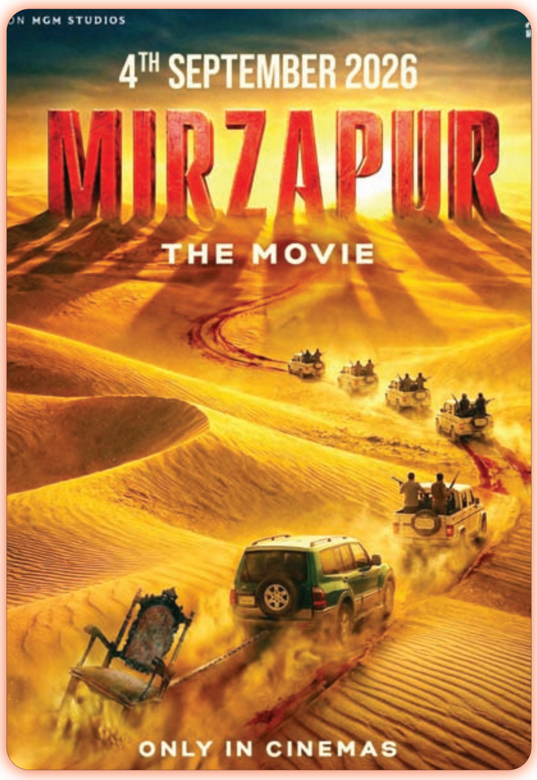

अमेजन प्राइम वीडियो पर 'मिर्जापुर' वेब सीरीज की जबरदस्त सफलता के बाद अब मेकर्स 'मिर्जापुरः द मूवी' लेकर आ रहे हैं। फैन्स के लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि फिल्म की रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। रणभूमि में सत्ता, लड़ाई और भौकाल की कहानी अब सिनेमाघरों में भी पर्दे पर दिखाई देगी। फिल्म गुरमीत सिंह के निर्देशन में तैयार की जा रही है और इसका निर्माण एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर ने किया है। सह-निर्माता के रूप में कासिम जगमगिया और विशाल रामचंदानी जुड़े हैं। मेकर्स ने रिलीज डेट का ऐलान करते हुए फिल्म का पोस्टर जारी किया, जिसमें लिखा है, अब देखिए भौकाल बड़े पर्दे पर 'मिर्जापुरः द मूवी' 4 सितंबर को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म में सीरीज के चर्चित किरदारों का जबरदस्त कॉम्बो दिखेगा। अली फजल (गुड्डू पंडित), पंकज त्रिपाठी (कालीन भैया) और दिव्येंदु (मुन्ना भैया) की वापसी दर्शकों के लिए खास आकर्षण होगी। इसके अलावा नई फिल्म में जितेंद्र कुमार, रवि किशन और अभिषेक बनर्जी जैसे नए चेहरे भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे।

बालाजी मोशन पिक्चर्स के साथ बॉलीवुड डेब्यू करेंगी
सुनीता आहूजा

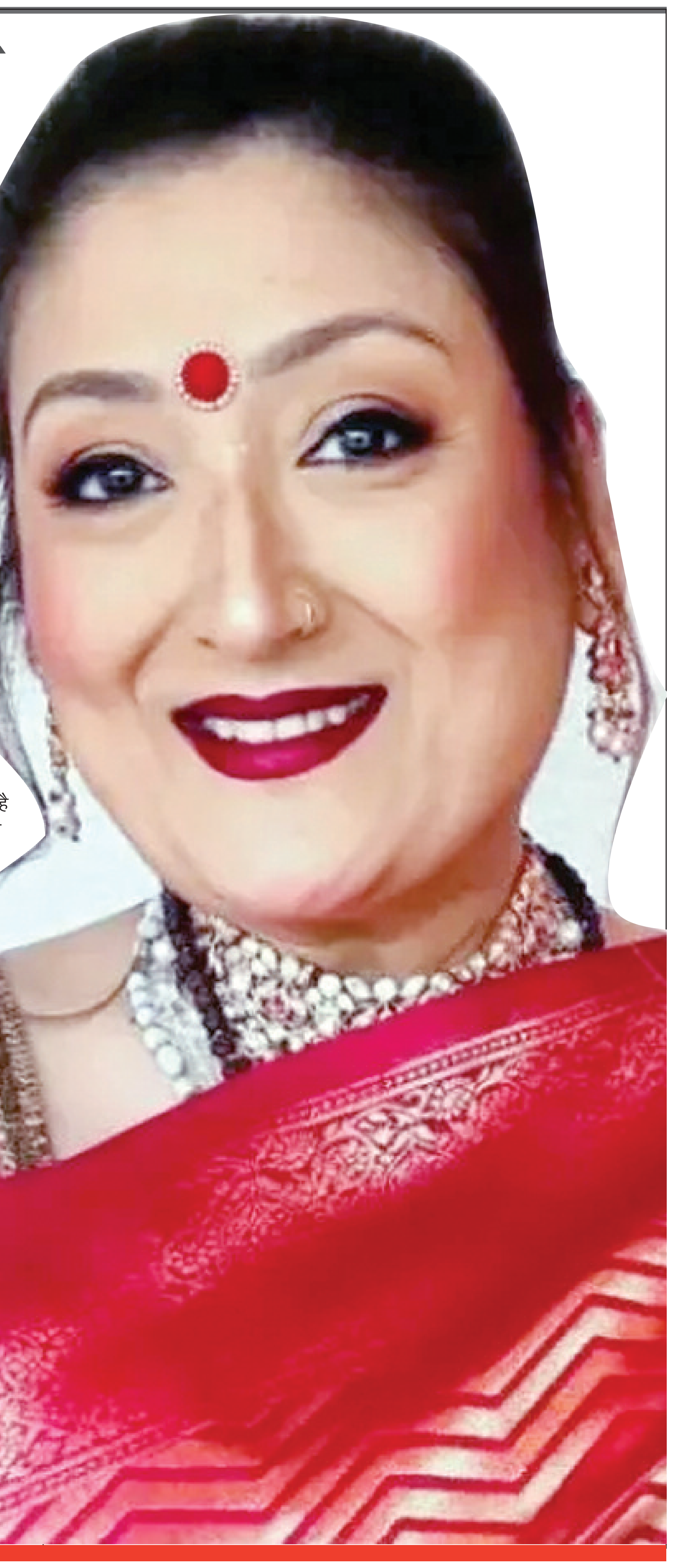

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने बेबाक अंदाज और हाजिरजवाबी के लिए अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। अब वह आधिकारिक तौर पर अभिनय की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। लंबे समय तक परिवार और निजी जीवन को प्राथमिकता देने के बाद सुनीता ने एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस बालाजी मोशन पिक्चर्स के साथ अपनी पहली हिंदी फिल्म साइन कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह इस फिल्म में एक अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी। सूत्रों के अनुसार, 58 वर्षीय सुनीता इस अनटाइटल्ड फिल्म की करीब 20 दिनों तक शूटिंग करेंगी। हालांकि वह पहले भी टीवी शोज, इवेंट्स और इंटरव्यू में दिखाई देती रही हैं, लेकिन यह प्रोजेक्ट उनके करियर की आधिकारिक बॉलीवुड शुरुआत माना जा रहा है। खास बात यह है कि सुनीता ने अब तक ग्लैमर इंडस्ट्री की चकाचौंध से दूरी बनाए रखी थी और कभी भी अपने पति की लोकप्रियता का सहारा लेकर फिल्मी करियर शुरू करने की कोशिश नहीं की। पिछले कुछ समय से सुनीता सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी से नई पहचान बना चुकी हैं। उनके पॉडकास्ट इंटरव्यू, सार्वजनिक कार्यक्रमों में बेबाक बयान और यूट्यूब चैनल ने उन्हें दर्शकों के बीच अलग पहचान दिलाई है। माना जा रहा है कि उनकी इसी लोकप्रियता को देखते हुए एकता कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म का हिस्सा बनाया। वहीं हाल ही में गोविंदा भी अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर फैली अफवाहों को लेकर चर्चा में रहे। उन्होंने इन खबरों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें एक साजिश बताया और कहा कि उनकी चुप्पी को गलत तरीके से लिया जा रहा था। अब सुनीता की फिल्मी पारी की शुरुआत के साथ यह स्टार कपल एक बार फिर सकारात्मक वजहों से खबरों में है।

बॉक्स ऑफिस पर 'बॉर्डर 2' स्थिर, 'मर्दानी 3' की हालत नाजुक

सनी देओल और वरुण धवन की युद्ध-ड्रामा फिल्म 'बॉर्डर 2' अपने दूसरे हफ्ते में भी सिनेमाघरों में दर्शकों को खींचने में सफल रही है। वीकेंड के मुकाबले कमाई में गिरावट के बावजूद फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और यह 300 करोड़ रुपये के क्लब पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी ओर रानी मुखर्जी की क्राइम-थ्रिलर 'मर्दानी 3' पहले ही हफ्ते में कमजोर कलेक्शन से जूझती नजर आ रही है। सैकनिल्क के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' ने अपने 13वें दिन (बुधवार) लगभग 4.88 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इससे पहले 12वें दिन फिल्म ने 6.69 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की थी। हालांकि नॉन-हॉलीडे के मद्देनजर गिरावट आई है लेकिन फिल्म ने अब तक कुल 319.98 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन हासिल कर लिया है। वहीं 'मर्दानी 3' की हालत निराशाजनक बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने अपने छठे दिन लगभग 2 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जबकि 5वें और 4वें दिन यह क्रमशः 2.6 करोड़ और 2.25 करोड़ रुपये रहा। लगातार गिरते आंकड़ों के साथ 'मर्दानी 3' अब तक कुल 24.25 करोड़ रुपये ही जुटा पाई है, जो इसके बजट की वसूली के लिहाज से चिंता का विषय है। दोनों फिल्में अपनी-अपनी राह पर बॉक्स ऑफिस पर आगे बढ़ रही हैं, जहां 'बॉर्डर 2' अपनी टेकिंग और दर्शक रुचि के बल पर मजबूत बनी हुई है, वहीं 'मर्दानी 3' को शुरुआती हफ्तों में ही बड़े संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है।

विदेश

संक्षिप्त खबरें

भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंकाई मछुआरों पर हमले के आरोपों को खारिज किया

कोलंबो। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने बृहस्पतिवार को भारतीय तटरक्षक बल द्वारा श्रीलंकाई मछुआरों के एक समूह पर कथित हमलों का खंडन किया। भारतीय उच्चायोग ने एक विज्ञप्ति में कहा, ''हमने इसका पता लगाया है और हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि भारतीय नौसेना या भारतीय तटरक्षक बल के किसी भी कर्मी ने ऐसा कोई हमला नहीं किया था।'' विज्ञप्ति में कहा गया है, ''भारत ने लगातार यह बात कही है कि मछुआरों की आजीविका संबंधी चिंताओं के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में बल प्रयोग का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए।'' श्रीलंका के मत्स्य पालन मंत्री रामलिंगम चंद्रशेखरन ने दो फरवरी को कहा था कि इस घटना को लेकर भारत सरकार के समक्ष विरोध दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस घटना की जानकारी भारतीय उच्चायोग को दे दी गई है। उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित वेन्नाप्पुवा के वेल्लामनकारया बंदरगाह से 29 जनवरी को तीन ट्रॉलर में 12 मछुआरे मछली पकड़ने निकले थे। इन मछुआरों पर कथित तौर पर भारतीय तटरक्षक बलों ने हमला किया था।

नाइजीरिया में इस्लामिक आतंकवादियों के हमले में 162 लोगों की मौत

सोकोतो (नाइजीरिया)। पश्चिमी नाइजीरिया के दो गांवों पर हथियारबंद चरमपंथियों के हमले में 162 लोग मारे गए। एक सांसद ने यह जानकारी की। क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद मोहम्मद उमर बायो ने बताया कि मंगलवार शाम को क्वारा राज्य के वोरो और नुकु गांवों को निशाना बनाकर हमले किए गए। उन्होंने बताया कि यह हमला नाइजीरिया में हाल के महीनों में हथियारबंद चरमपंथियों के सबसे घातक हमलों में से एक है। बायो ने कहा कि ये हमले इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकवादी संगठन लकुरावा द्वारा किए गए हैं। हालांकि इन हमलों की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली है। क्वारा राज्य में रेड क्रॉस के सचिव अयोदेजी इमैनुअल बाबाओमो ने कहा कि संगठन उन सुदूर स्थानों पर पहुंचने में असमर्थ रहा है जहां ''कई लोग मारे गए''। यह क्षेत्र राज्य की राजधानी से लगभग आठ घंटे की दूरी पर और नाइजीरिया की बेनिन के साथ लगती सीमा के निकट है। स्थानीय टेलीविजन पर प्रसारित घटनास्थल के फुटेज में जमीन पर खून से लथपथ शव दिख रहे हैं जिनमें से कुछ के हाथ बंधे हुए हैं, साथ ही जलते हुए घर भी नजर आ रहे हैं। राज्य के गवर्नर अब्दुल रहमान अब्दुल रजाक ने इस हमले को राज्य में हथियारबंद चरमपंथियों के खिलाफ जारी सैन्य अभियानों के जवाब में ''आतंकवादी गुटों की हताशापूर्ण कार्रवाई'' बताया।

चुनाव नज़दीक आते ही ओली पर दबाव बढ़ा

रणनीतिक गठबंधनों की चर्चा फिर तेज

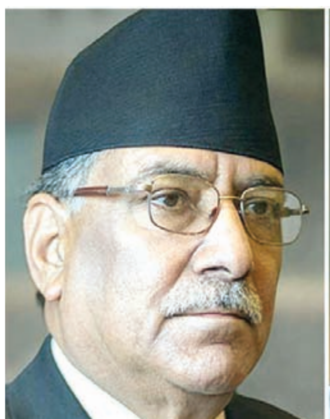

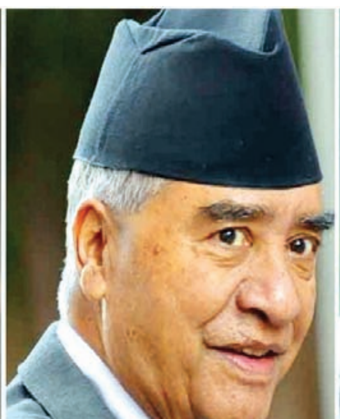

काठमांडू। अगले माह 5 मार्च को होने वाले चुनाव में अब समय कम रह गया है जिससे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएन-यूएमएल) पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सितंबर में हुए जेन-जी आंदोलन के बाद पैदा हुआ राजनीतिक असर अब चुनावी परिदृश्य को स्पष्ट रूप से प्रभावित करने लगा है। पिछले साल 8 और 9 सितंबर को हुए जेन-जी प्रदर्शनों के दौरान हुई मानवीय और भौतिक क्षति को लेकर यूएमएल लगातार आलोचना के घेरे में है। उस समय पार्टी अध्यक्ष और तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। आलोचकों का आरोप है कि ओली ने हिंसा की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की और यही आरोप पार्टी का पीछा करता रहा है। हाल ही में ओली ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जान गंवाने वाले 19 लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की लेकिन इससे जनआक्रोश शांत नहीं हो सका। ज्यादातर प्रमुख दलों के स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के फैसले के बीच यूएमएल की चुनौतियां और बढ़ गई हैं। काठमांडू महानगर के पूर्व मेयर बालेन शाह का झापा-5 से चुनाव लड़ने का निर्णय ओली पर अतिरिक्त दबाव बना रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र परंपरागत रूप से उनका गढ़ माना जाता रहा है। वहीं, यूएमएल के महासचिव शंकर पोखरेल भी दांग-2 में कड़े मुकाबले का सामना कर रहे हैं, जिससे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर खतरे की आशंका बढ़ गई है। इसी पृष्ठभूमि में ओली ने कुछ चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों में सीमित चुनावी सहयोग की संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी हैं। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष गगन थापा द्वारा किसी भी प्रकार के गठबंधन को स्पष्ट रूप से नकारे जाने के बाद, ओली कथित तौर पर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) के साथ समन्वय की संभावनाएं टटोल रहे हैं। उधर, एनसीपी के समन्वयक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचंड' पर भी राजनीतिक दबाव दिखने लगा है। उन्होंने हाल ही में एक भावुक वीडियो संदेश जारी कर संकेत दिया कि वे प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में नहीं हैं और युवा पीढ़ी को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। यूएमएल-एनसीपी संभावित समन्वय की अटकलों को तब और बल मिला जब अंतरिम सरकार ने देशभर में 80 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात कर यह स्पष्ट कर दिया कि 5 मार्च के चुनाव स्थगित नहीं होंगे। ऐसे में ओली और प्रचंड दोनों ही अपने-अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश में जुटे नजर आ रहे हैं। ओली जहां झापा में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, वहीं प्रचंड रुकुम पूर्व में अपेक्षाकृत सुरक्षित महसूस करने के बावजूद देशव्यापी बेहतर नतीजों के रास्ते तलाश रहे हैं। ओली एनसीपी या राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (आरपीपी) के साथ गठबंधन के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। 2022 के चुनावों में यूएमएल और आरपीपी के बीच सफल समन्वय देखने को मिला था, जिसमें ओली ने झापा-5 और आरपीपी अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन ने झापा-3 से जीत हासिल की थी। हालांकि, लिंगदेन ने संकेत दिया है कि आरपीपी इस बार स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी, जिससे ओली का रुझान एनसीपी की ओर बढ़ता दिख रहा है।

एनसीपी नेताओं ने पुष्टि की है कि ओली ने चुनावी सहयोग का प्रस्ताव रखा है, हालांकि अभी तक कोई औपचारिक निर्णय नहीं हुआ है। प्रचंड के सचिवालय का कहना है कि बातचीत केवल कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में सहयोग की संभावना तक सीमित रही है, न कि देशव्यापी गठबंधन पर। स्वयं प्रचंड ने भी साक्षात्कारों में संकेत दिया है कि रणनीतिक समन्वय से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, एनसीपी के भीतर विरोध भी मजबूत है। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल और भीम रावल ने चेतावनी दी है कि यूएमएल के साथ गठबंधन पार्टी को और कमजोर कर सकता है, विशेषकर जेन-जी आंदोलन को लेकर ओली के खिलाफ जन-असंतोष को देखते हुए। उनका कहना है कि जब तक ओली सार्वजनिक रूप से अपने पिछले कदमों के लिए माफी नहीं मांगते, किसी भी तरह का गठबंधन राजनीतिक रूप से नुकसानदेह होगा।

माधव नेपाल ने कहा कि फिलहाल यूएमएल के साथ किसी भी तरह के गठबंधन या समन्वय की संभावना नहीं है और सभी निर्णय आंतरिक परामर्श के जरिए लिए जा रहे हैं। भीम रावल ने भी यही रुख दोहराते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में एनसीपी यूएमएल के साथ आगे नहीं बढ़ेगी और यूएमएल नेताओं पर पार्टी को कमजोर करने के लिए अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया। यूएमएल के भीतर भी मतभेद दिखाई दे रहे हैं। जहां वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से गठबंधन वार्ता से इनकार कर रहे हैं, वहीं ओली के सचिवालय से जुड़े कुछ लोग स्वीकार करते हैं कि प्रचंड के साथ बातचीत हुई है। अटकलें हैं कि सीट आधारित सहयोग के तहत यूएमएल रुकुम पूर्व और अन्य क्षेत्रों में एनसीपी उम्मीदवारों का समर्थन कर सकती है, जिसके बदले एनसीपी झापा-5 में ओली और दांग-2 में पोखरेल को समर्थन दे सकती है।

बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री से निपटने में अब भी नाकाम

होबार्ट। 'ऑस्ट्रेलियन सेंटर टू काउंटर चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन' को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) से जुड़े करीब 83,000 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकतर मामले मुख्यधारा के डिजिटल मंच से संबंधित थे। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है। मुख्यधारा के मंच पर खुले तौर पर हो रहे बाल शोषण के इस परिप्रेक्ष्य में ई-सेफ्टी आयुक्त जूली इनमैन ग्रांट ने गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा सहित अन्य बड़ी टेक कंपनियों से हर छह महीने में पारदर्शिता रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता सुनिश्चित की है। नवीनतम रिपोर्ट में ज्ञात बाल शोषण सामग्री की पहचान में कुछ प्रगति दर्ज की गई है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से उत्पन्न सामग्री, लाइव-स्ट्रीमिंग के माध्यम से शोषण, ऑनलाइन ग्रूमिंग और बच्चों व वयस्कों के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले शामिल हैं। रिपोर्ट में गंभीर सुरक्षा खामियों की ओर भी इशारा किया गया है, जो उपयोगकर्ताओं, विशेषकर बच्चों, को जोखिम में डालती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, केवल पारदर्शिता पर्याप्त नहीं है और नुकसान दर्ज करने के बजाय बेहतर समाधान के माध्यम से उन्हें रोकने की आवश्यकता है। ई-सेफ्टी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पारदर्शिता रिपोर्ट नियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अहम हैं, लेकिन तकनीकी क्षमता और कंपनियों द्वारा उठाए गए वास्तविक कदमों के बीच अब भी अंतर बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, स्नैपचैट की मूल कंपनी स्नैप ने बाल यौन शोषण से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई का औसत समय 90 मिनट से घटाकर 11 मिनट कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने आउटलुक में ज्ञात शोषण सामग्री की पहचान के दायरे का विस्तार किया है। इसके बावजूद, मेटा और गूगल ने मैसेंजर और गूगल मीट जैसी वीडियो कॉलिंग सेवाओं में लाइव-स्ट्रीम में शोषण की निगरानी नहीं कर रही हैं, जबकि उनके अन्य मंच पर पहचान उपकरण मौजूद हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एप्पल और डिस्कॉर्ड सक्रिय पहचान प्रणाली लागू करने में विफल रहे हैं। एप्पल लगभग पूरी तरह उपयोगकर्ताओं की शिकायतों पर निर्भर है। एप्पल, डिस्कॉर्ड, गूगल चैट, मीट और मैसेजेज, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स तथा स्नैप फिलहाल बच्चों के यौन शोषण और ब्लैकमेल की पहचान के लिए उपलब्ध सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आयुक्त ने लाइव वीडियो और एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म को सबसे बड़ी चिंता का विषय बताया है।

पुतिन-शी ने आर्थिक सहयोग, अमेरिका से रिश्तों और वैश्विक हालात पर चर्चा की

मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की और दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक सहयोग तथा अमेरिका के साथ संबंधों पर चर्चा की। पुतिन ने इस साल चीन की यात्रा का निमंत्रण भी स्वीकार किया। पुतिन और चिनफिंग के बीच यह बातचीत ऐसे समय हुई है जब शी और पश्चिमी देशों के नेताओं के बीच कई बैठकें हो रही हैं। ये नेता यूक्रेन युद्ध को लेकर मतभेदों के बावजूद चीन के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपीय नेता वर्षों से चीन पर रूस को दिए जा रहे समर्थन को समाप्त करने का दबाव बना रहे हैं, वहीं चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। रूसी सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित अपने शुरुआती संबोधन में पुतिन ने कहा, '' मैं एक बार फिर यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारे देशों की संप्रभुता और सुरक्षा, लोगों की सामाजिक-आर्थिक भलाई और अपने विकास का रास्ता खुद चुनने के हमारे साझा प्रयासों को मेरा दृढ़ समर्थन है।' पुतिन ने कहा, ''दुनिया में बढ़ती उथल-पुथल के बीच रूस और चीन के बीच विदेश नीति का तालमेल स्थिरता लाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है।'' वहीं शी ने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि वह और पुतिन द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की योजनाओं पर चर्चा करेंगे और 'बड़े रणनीतिक मुद्दों' पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को 'ऐतिहासिक अवसर' का उपयोग करते हुए रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करना चाहिए। चीनी सरकारी प्रसारक 'सीसीटीवी' की एक खबर में बताया गया कि शी ने बुधवार को वसंत ऋतु का पहला दिन बताते हुए कहा कि नए आरंभ का प्रतीक माने जाने वाले इस दिन वह पुतिन के साथ मिलकर ''चीन-रूस संबंधों का एक नया खाका'' तैयार करना चाहते हैं।